सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 167, नई दिल्ली । मंगलवार, 27 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

03 दिल्ली इतनी असुरक्षित है कि कहीं भी जान जा सकती है।- देवेन्द्र यादव

06 खाद्य कीमतों पर सतर्कता जरूरी

08 ममता महांत बीजेपी का राज्यसभा उम्मीदवार

क्या आप जानते हैं?

संजय बाटला

नई दिल्ली। राजस्व में इजाफा करवाने के उद्देश्य के लिए परिवहन विभाग में आसीन आला अधिकारी **(परिवहन आयुक्त और विशेष परिवहन आयुक्त)** सभी तकनीकी पदो से तकनीकी अधिकारी को हटाकर राजस्व इजाफा करवाने के लिए सरकार में नियुक्त गैर तकनीकी अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को दरकिनार कर लगा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव की भी सहमति शामिल हैं

दिल्ली के महामहिम पद पर आसीन उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग मिलकर साजिश के तहत दिल्ली परिवहन विभाग से तकनीकी अधिकारियों को हटाकर / वीआरएस लेने पर मजबूर कर अपनी इच्छा के गैर तकनीकी अधिकारियों को लाकर तकनीकी पदो पर आसीन कर रहे हैं जब की अन्य भारत देश के राज्य जनता की सड़को पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी अधिकारियों की भर्ती कर रही हैं। **यहां प्रश्न यह उठता है की एक तरफ तो सब को यह दिखाया जा रहा है की दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार एक दूसरे के विरोधी हैं।** पर

दिल्ली में सड़को और वाहनों मे जनता की सुरक्षा को,

दिल्ली में सड़को और वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा को,

दिल्ली में व्यवसायिक वाहन क्षेत्र में जुड़े एकल मालिकों को नष्ट करवाने में,

बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने में

सभी नियमों, दिशा निर्देशों, कानूनी राय को दरकिनार कर सभी **(उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार और आला अधिकारी परिवहन विभाग)** एकजुट होकर साजिश रच कर कार्य करते नजर आ रहे हैं और **सबका उद्देश्य कैसे जनता से लूटकर राजस्व में इजाफा किया जाए और बड़े व्यवसायिक घरानों और कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाए** भी एक है फिर कैसे दोनो एक दूसरे के विरोधी जो जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **इसका एक और सबूत यह भी है की 15 अगस्त को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को ध्वजारोहण करने से जिस कारण से रोका गया वह परिवहन मंत्री द्वारा ध्वजारोहण के लिए कैसे हट गया** यहां यह स्पष्ट नजर आ रहा है की दिल्ली में आसीन किसी भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता और परिवहन विभाग के आला अधिकारी को दिल्ली की जनता की सुरक्षा से, दिल्ली की सड़को पर लगते जामो से, होने वाली दुर्घटनाओं, हादसो, वाहन की चोरियों और बढ़ते हुए प्रदूषण से कुछ लेना देना नहीं है उन्हें तो सिर्फ **राजस्व में किसी भी तरीके से इजाफे से मतलब है।** आप पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड उठाकर या आरटीआई लगाकर भी पता कर सकते है की परिवहन विभाग के अंदर आला अधिकारी पर वही लम्बे समय तक आसीन रहा है जिसने राजस्व में नियमों को दरकिनार करके इजाफा करवाया वर्ना मात्र 4 से 6 महीने में ही आसीन अधिकारी को परिवहन विभाग के आला अधिकारी पद से हटा दिया जाता रहा है।

यह सब आपको इस लिए बता रहे है क्योंकि राजस्व में इजाफा करवाने के उद्देश्य के लिए परिवहन विभाग में आसीन आला अधिकारी **(परिवहन आयुक्त और विशेष परिवहन आयुक्त)** सभी तकनीकी पदो से तकनीकी अधिकारी को हटाकर राजस्व इजाफा करवाने के लिए सरकार में नियुक्त गैर तकनीकी अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को दरकिनार कर लगा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव की भी सहमति शामिल हैं। **आपकी जानकारी के लिए बता दूं एक दिल्ली का परिवहन विभाग है जो दिन-प्रतिदिन एम.वी.आई (तकनीकी अधिकारी) की संख्या में कटौती करने पर लगा है जबकि वाहनों का घनत्व दिन दूनी रात चौगुनी की दर से बढ़ रहा है वहीं अन्य प्रान्तों की सरकारें जहा दिल्ली की अपेक्षा वाहनों का घनत्व काफी कम होने के बावजूद तकनीकी निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि कर रही हैं। उनका कहना और उद्देश्य सष्ट है "सड़क सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए एआरटीओ और एमवीआई पदो के अधिकारियों का अधिक से अधिक होना आवश्यक है"** गृह मंत्री भारत सरकार, उच्चतम न्यायालय भारत सरकार और उच्च न्यायालय दिल्ली संज्ञान ले क्योंकि **दिल्ली सिर्फ एक राज्य नही भारत देश की राजधानी है और यहां सड़क सुरक्षा, एवम गुणवता के अनुसार व्यवसायिक वाहन सेवा सुरक्षित होना अति आवश्यक है पर कार्यरत आला अधिकारियों के रहते सुरक्षा और सुरक्षित वाहन सेवा की आशा दिन प्रतिदिन कम हो रही हैं।**

डीएमआरसी का नया प्लान, मार्केट में मिलेंगे दिल्ली मेट्रो के ब्रांडेड कपड़े; राजस्व बढ़ने से यात्रियों को भी होगा फायदा

दिल्ली मेट्रो अब बाजार में अपने ब्रांड नाम से उत्पाद उतारने की तैयारी कर रहा है। डीएमआरसी ने कारोबारियों और निजी फर्म से अभिरुचि प्रस्ताव मांगे हैं। यदि कारोबारियों व निजी फर्म दिलचस्पी दिखाते हैं तो बाजार में डीएमआरसी ब्रांड के कपड़े सहायक सामान सहित कई तरह के उत्पाद मिल सकते हैं। डीएमआरसी को इस पहल से राजस्व बढ़ने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो के मोबाइल ऐप से जरूरत की चीजें ऑनलाइन सामान खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद अब डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल निगम) बाजार में भी अपने ब्रांड नाम से उत्पाद उतारने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि डीएमआरसी ने कारोबारियों और निजी फर्म से अभिरुचि प्रस्ताव मांगा है। इसलिए इच्छुक कारोबारी व कंपनियां डीएमआरसी को आवेदन दे सकते हैं।

डीएमआरसी की इस योजना में यदि कारोबारियों व निजी फर्म दिलचस्पी दिखाई तो बाजार में डीएमआरसी ब्रांड के कपड़े, सहायक सामान सहित कई तरह के उत्पाद बाजार में मिल सकते हैं।

डीएमआरसी को इस पहल से राजस्व बढ़ने की उम्मीद

डीएमआरसी का कहना है कि अभिरुचि प्रस्ताव देने वाले निजी फर्मों के साथ एक समझौता किया जाएगा। इसके तहत उन्हें डीएमआरसी ब्रांड से उत्पाद बनाने और बेचने की की स्वीकृति होगी। डीएमआरसी को इस पहल से राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। मेट्रो में प्रतिदिन लाखों यात्री सफर करते हैं। डीएमआरसी मेट्रो की इस लोकप्रियता का लाभ उठाकर ऐसे ब्रांडेड उत्पाद लाने की कोशिश में जुटा है जो लोगों को पसंद आए। डीएमआरसी का कहना है कि इससे राजस्व के साथ-साथ लोगों के बीच दिल्ली मेट्रो का ब्रांड भी दिखेगा।

दिल्ली मेट्रो के आय का मुख्य साधन यात्री किराया

उल्लेखनीय है कि दिल्ली मेट्रो के आय का मुख्य साधन यात्री किराया है। किराए के अलावा डीएमआरसी विभिन्न शहरों में मेट्रो विस्तार परियोजना परियोजनाओं में कंसल्टेंसी सेवा, संपत्ति विकास, मेट्रो स्टेशनों पर लगे स्टॉल और कई अन्य माध्यमों से भी राजस्व अर्जित करता है।

डीएमआरसी अपना राजस्व बढ़ाने के लिए कई अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। ताकि यात्रियों पर ज्यादा किराए का बोझ न बढ़े। इसी क्रम में डीएमआरसी ने बाजार में अपने ब्रांड नाम से उत्पाद उतारने की कोशिश कर रहा है।

दिल्ली मेट्रो फेज-4 के कंस्ट्रक्शन प्लान में आया बदलाव

69 पेड़ों को बचाने के लिए डीएमआरसी ने बनाई खास योजना

डीएमआरसी ने जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम मार्ग कॉरिडोर पर 69 पेड़ों की कटाई से बचने के लिए अपनी कंस्ट्रक्शन प्लान को फिर से डिजाइन किया है। इससे पहले इन पेड़ों को काटने के लिए भी अनुमति मांगी गई थी। इसमें देरी हो रही थी। फेज-4 के लिए 15508 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है। इनमें से 5003 पेड़ काटे गए और 7000 से अधिक लगाए गए।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मार्ग कॉरिडोर पर 69 पेड़ों को बचाने के लिए अपनी फेज-4 के कंस्ट्रक्शन प्लान को फिर से डिजाइन किया है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि इस फेज के लिए दिल्ली भर में कुल मिलाकर 15,508 पेड़ों को काटने की अनुमति प्राप्त हुई थी और मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर पर 71 और पेड़ों को काटने के लिए मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "डीएमआरसी ने जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम मार्ग कॉरिडोर पर 69 पेड़ों की कटाई से बचने के लिए अपनी कंस्ट्रक्शन प्लान को फिर से डिजाइन किया है। इससे पहले, इन पेड़ों को काटने के लिए भी अनुमति मांगी गई थी।" अधिकारी ने कहा, "कुल मिलाकर फेज-4 के निर्माण के लिए दिल्ली भर में 15,508 पेड़ों को काटने की अनुमति मिल गई है। इनमें से 5,003 पेड़ काटे गए हैं और 7,000 से अधिक को लगाया गया है।"

प्रत्येक पेड़ काटने पर 10 पेड़ लगाने का प्रावधान

डीएमआरसी के नियमों में काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए 10 पेड़ लगाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पेड़ों के काटने और लगाने की योजना बनाते समय पेड़ों वाले क्षेत्रों से बचने के सभी प्रयास किए जाते हैं। हालांकि, पेड़ों की कटाई की अनुमति मिलने में देरी के कारण फेज-4 के सभी तीन प्राथमिकता वाले कॉरिडोर में भी देरी हुई है। इस फेज का काम दिसंबर 2019 में शुरू हुआ और COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित हुआ।

DMRC फिलहाल तीन कॉरिडोर का कर रहा निर्माण

डीएमआरसी परियोजना के तीन प्राथमिकता वाले कॉरिडोर के तहत 45 स्टेशनों तक फैले 65.2 किमी पर निर्माण कार्य कर रहा है। इसमें जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मार्ग (28.92 किमी), मजलिस पार्क-मौजपुर (12.55 किमी) और एयरोसिटी-तुगलकाबाद (23.62 किमी) कॉरिडोर शामिल हैं। इसे 'सिल्वर लाइन' के रूप में बनाया जा रहा है। यह वायलेट लाइन और एयरपोर्ट लाइन को जोड़ता है।

दिल्ली मेट्रो ने लगाए इतने पेड़

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, डीएमआरसी ने फेज एक के निर्माण के दौरान 13,858 पेड़ काटे और 3,584 पेड़ों को लगाया, जो 1998 में शुरू हुआ और 2005 में समाप्त हुआ। इसके 65 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क में 59 स्टेशन शामिल थे। 2005 और 2011 के बीच किए गए फेज 2 में, DMRC ने 17,997 पेड़ों को काटा और 3,052 पेड़ों को लगाया। चरण 2 में 125 किमी में 89 स्टेशन बनाए गए थे।

फेज 3 को पूरा होने में 2011 से नौ साल लग गए। DMRC ने 11,872 पेड़ काटे और 506 पेड़ों को लगाया। फेज 3 में 109 स्टेशनों वाले 160 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क का निर्माण शामिल था।

बुलेट ट्रेन सा सफर... एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं; सराय काले खां स्टेशन की खूबियां जीत लेंगी दिल

परिवहन विशेष न्यूज

हा है। चर्चा है कि टोल प्लाजा का निर्माण पूरा होते ही जितने किलोमीटर तक प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, उतनी दूरी का टोल टैक्स वसूला जाएगा। दो महीने में टोल प्लाजा पूरी तरह तैयार हो जाएगा।

विकसित हो चुकी हैं लगभग 100 सोसायटियां

एक्सप्रेस-वे के आसपास लगभग 100 सोसायटियां अब तक विकसित हो चुकी हैं। कई गांव व कॉलोनियां एक्सप्रेस-वे के आसपास हैं। इनमें लाखों लोग रहते हैं। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से यह कहा जा रहा है कि द्वारका एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट पूरा होते ही खेड़कीदौला टोल प्लाजा हटाया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है।

यदि हटाने का विचार होता तो अब तक पचगांव में टोल प्लाजा का निर्माण शुरू हो जाता। पचगांव के नजदीक दिल्ली-जयपुर हाईवे पर टोल प्लाजा बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने जमीन देने पर अपनी सहमति दे चुकी है। उन लोगों के ऊपर दोहरी मार पड़ने की आशंका है।

द्वारका एक्सप्रेस-वे पर टोल वसूली से पहले खेड़कीदौला टोल प्लाजा हटाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह लाखों लोगों के साथ धोखा है। इस बारे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में मामले से संबंधित एक जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।

पिछले वर्ष ही पूरा होना था प्रोजेक्ट

लगभग नौ हजार करोड़ रुपये की लागत से द्वारका एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। गुरुग्राम हिस्से का काम एलएंडटी नामक कंपनी लगभग पूरी कर चुकी है। दिल्ली हिस्से की जिम्मेदारी जय कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के पास है।

भूमिगत बनाया जा रहा चार किलोमीटर भाग

गत वर्ष ही प्रोजेक्ट पूरा होना था, लेकिन अब इस वर्ष के अंतर्गत पूरा होने की उम्मीद है। एक्सप्रेस-वे का 18.9 किलोमीटर हिस्सा गुरुग्राम में, बाकी 10.1 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में है। इसमें से 23 किलोमीटर भाग एलिवेटेड और लगभग चार किलोमीटर भूमिगत बनाया जा रहा है।

दिल्ली में पहला भाग गुरुग्राम-दिल्ली सीमा से बिजवासन तक लगभग 4.20 किलोमीटर का है। दूसरा भाग बिजवासन से शिवमूर्ति तक 5.90 किलोमीटर का है। गुरुग्राम इलाके में पहला भाग खेड़कीदौला टोल प्लाजा के नजदीक से बसई-धनकोट के नजदीक तक लगभग 8.76 किलोमीटर का है।

दूसरा भाग बसई-धनकोट के नजदीक से गुरुग्राम-दिल्ली सीमा तक लगभग 10.2 किलोमीटर का है। द्वारका एक्सप्रेस-वे से लोग सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

गणेश चतुर्थी पर भद्रावास योग का हो रहा है निर्माण, दूर होंगे सभी दुख एवं कष्ट

धार्मिक मत है कि भगवान गणेश की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिष भी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह देते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से करियर और कारोबार को नया आयाम मिलता है। भगवान गणेश की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। यह पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात समेत देशभर में गणेशोत्सव का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मत है कि भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही आर्थिक तंगी से भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिषियों की मानें तो गणेश चतुर्थी पर भद्रावास का शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही कई अन्य मंगलकारी शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में भगवान गणेश की पूजा करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही भगवान गणेश की कृपा साधक पर बरसेगी। आइए, शुभ मुहूर्त एवं योग जानते हैं।

भद्रावास योग (Bhadravas Yog)

ज्योतिषियों की मानें तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 07 सितंबर को प्रातः काल 04 बजकर 20 मिनट पर भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। वहीं, गणेश चतुर्थी के दिन संध्याकाल 05 बजकर 37 मिनट पर भद्रावास का समापन होगा। इस दौरान भद्रा पाताल लोक में रहेंगी। सनातन शास्त्रों में निहित है कि भद्रा के पाताल में रहने के दौरान पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का कल्याण होता है। इस शुभ योग में भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सकल दुख एवं कष्ट दूर हो जाएंगे।

गणेश चतुर्थी शुभ योग (Ganesh Chaturthi Shubh Yog)

ज्योतिषियों की मानें तो गणेश चतुर्थी पर दुर्लभ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग दिन भर है। वहीं, इस शुभ योग का समापन रात 11 बजकर 17 मिनट पर होगा। इसके बाद इंद्र योग का संयोग बनेगा। वहीं, गणेश चतुर्थी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण दोपहर 12 बजकर 34 मिनट से हो रहा है। इस तिथि का समापन 08 सितंबर को सुबह 06 बजकर 03 मिनट पर होगा।

पंचांग

सूर्योदय - सुबह 06 बजकर 02 मिनट पर
सूर्यास्त - शाम 06 बजकर 35 मिनट पर
चन्द्रोदय- सुबह 09 बजकर 30 मिनट पर
चंद्रास्त- शाम 08 बजकर 44 मिनट पर
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04 बजकर 31 मिनट से 05 बजकर 16 मिनट तक
विजय मुहूर्त - दोपहर 02 बजकर 24 मिनट से 03 बजकर 14 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त - शाम 06 बजकर 35 मिनट से 06 बजकर 58 मिनट तक
निशिता मुहूर्त - रात्रि 11 बजकर 56 मिनट से 12 बजकर 42 मिनट तक

ग्लोइंग त्वचा के लिए घर पर बनाएं ये 4 मुल्तानी मिट्टी का मास्क, जानें इसके फायदे

अगर आप भी ग्लोइंग त्वचा पाना चाहते हैं तो आप भी मुल्तानी मिट्टी से बने हुए यह मास्क घर पर जरुर बनाएं। यह मास्क ग्लोइंग स्किन के साथ-साथ चेहरे की गंदगी को भी गहराई से साफ करते हैं। मुल्तानी मिट्टी मास्क लगाने से स्किन को कई जबरदस्त फायदे देखने को मिलते हैं।

त्वचा के लिए असंख्य लाभों के कारण त्वचा की देखभाल में मिट्टी के मास्क का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। मुल्तानी मिट्टी मास्क एक लोकप्रिय त्वचा देखभाल उपचार है जो त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार के लिए खनिज युक्त मिट्टी के प्राकृतिक लाभों का उपयोग करता है। अक्सर मिट्टी के जमाव से प्राप्त, ये मास्क मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे खनिजों से भरे होते हैं, जो त्वचा पर विभिन्न चिकित्सीय प्रभाव प्रदान कर सकते हैं।

मुल्तानी मिट्टी मास्क के लाभ

गहरी सफाई करता

मिट्टी के मास्क अपने अवशोषक गुणों के कारण त्वचा से अशुद्धियों और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। यह गहरी सफाई प्रभाव बंद छिद्रों को साफ़ करने और मुँहासे को कम करने में मदद कर सकता है।

एक्सफोलिएट करता

कई मिट्टी की प्राकृतिक बनावट कोमल एक्सफोलिएशन प्रदान करती है, मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाती है और त्वचा को चिकना और चमकदार बनाती है।

त्वचा को टाइट रखता है

मड मास्क त्वचा को कसने और मजबूत बनाने, छिद्रों की उपस्थिति को कम करने और अधिक युवा लुक देने में मदद कर सकता है।

स्किन को डिटॉक्स करता

मिट्टी में मौजूद खनिज अतिरिक्त तेल और अशुद्धियों को बाहर निकालकर त्वचा को विषहरण करने में मदद कर सकते हैं, जिससे वे तैलीय और मुँहासे-प्रवण त्वचा के प्रकारों के लिए फायदेमंद बन जाते हैं।

सुखदायक और शांत

कई मिट्टी के मास्क में प्राकृतिक सूजन-रोधी गुण होते हैं जो चिढ़ या सूजन वाली त्वचा को शांत कर सकते हैं, जिससे वे संवेदनशील त्वचा के प्रकारों के लिए भी उपयुक्त हो जाते हैं।

ये 4 मुल्तानी मास्क

साधारण क्ले मास्क

सामग्री:

-2 बड़े चम्मच बेंटोनाइट क्ले या हरी मिट्टी
-2 बड़े चम्मच पानी या सेब का सिरका

बनाने का तरीका

- मिट्टी को पानी या सेब के सिरके के साथ तब तक मिलाएं जब तक आपको एक चिकना पेस्ट न मिल जाए।
- अपने चेहरे पर लगाएं और लगभग 10-15 मिनट तक लगा रहने दें।
- गर्म पानी से धो लें और अपने चेहरे को थपथपाकर सुखा लें।

क्ले और शहद का मास्क

सामग्री

- 2 बड़े चम्मच क्ले
- 1 बड़ा चम्मच शहद

बनाने का तरीका

- क्ले को शहद का साथ मिक्स कर लें।
- अपने चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें।
- गर्म पानी से धो लें और फिर मॉइस्चराइजर लगा लें।

मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा मास्क

सामग्री

-2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी
-1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल

बनाने का तरीका

- मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल को मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें।
- अपने चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट तक लगा रहने दें।
- गुनगुने पानी से धो लें।

मुल्तानी मिट्टी और दही का मास्क

-2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी
-1 चम्मच दही

बनाने का तरीका

- मुल्तानी मिट्टी को दही के साथ तब तक मिलाएं जब तक आपको एक मलाईदार स्थिरता न मिल जाए।
- अपने चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें।

- गर्म पानी से धो लें और थपथपा कर सुखा लें।

यह मास्क त्वचा की विभिन्न समस्याओं में मदद करते हैं, लेकिन किसी भी एलर्जी या संवेदनशीलता की जांच के लिए पहले पैच टेस्ट करना सुनिश्चित करें।

आपके आधार कार्ड का तो नहीं हो रहा गलत इस्तेमाल? इन सिंपल स्टेप्स से करें चेक और ऑनलाइन शिकायत

आधार का इस्तेमाल आप सरकारी काम, बैंक से जुड़े काम और मेन डॉक्यूमेंट के तौर पर भी करते हैं। इन दिनों आधार कार्ड को लेकर कई स्कैम सामने आ रहे हैं। आधार का स्कैमर्स गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपना आधार कैसे सुरक्षित रखें और इसके गलत इस्तेमाल को कैसे रोंके। ये अहम समस्या हो जाती है।

भारत के नागरिकों के लिए बेहद जरूरी

पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड है। जो इस बात की पुष्टि करता है कि आप भारतीय नागरिक हैं इसके अलावा आधार का इस्तेमाल आप सरकारी काम, बैंक से जुड़े काम और मेन डॉक्यूमेंट के तौर पर भी करते हैं। इन दिनों आधार कार्ड को लेकर कई स्कैम सामने आ रहे हैं। आधार का स्कैमर्स गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपना आधार कैसे सुरक्षित रखें और इसके गलत इस्तेमाल को कैसे रोंके। ये अहम समस्या हो जाती है।

अगर आपके साथ भी आधार से जुड़ी कोई भी स्कैम होता है या हुआ है और आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इन सिंपल स्टेप्स से ऑनलाइन इसकी शिकायत कर सकते हैं।

क्या है आधार कार्ड स्कैम

आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल

आजकल काफी आम हो गया है। जब स्कैमर्स आपके आधार को गलत तरीके से एक्सेस कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आधार कार्ड स्कैम में आता है।

स्कैमर्स आधार सिस्टम पर एक्सेस पाने की कोशिश करते हैं। जिससे यूजर्स को वित्तीय नुकसान के साथ पहचान की चोरी और पर्सनल डेटा का भी नुकसान होता हैं। इससे आपके बैंक डिटेल भी उनके पास जा सकती है। उन्हें कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ा सकता है।

चेक करें आधार के दुरुपयोग

अगर आपका आधार गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो आपके पास एक तरीका है, जिससे आप इसकी जांच कर सकते हैं।

सबसे पहले myAadhar पोर्टल पर

जाएं, और अब अपने आधार नंबर, कैप्चा कोड और ओटीपी से लॉगिन करें।

फिर इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी डालें और लॉगिन करें। फिर ऑथेंटिकेशन हिस्टरी (Authentication History) को सेलेक्ट करें। अब अपने आधार के इस्तेमाल की हिस्ट्री देखने के लिए तारीख चुनें। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि है तो उसे UIDAI वेबसाइट पर रिपोर्ट करें।

कैसे करें शिकायत

अगर आप अपने आधार के गलत इस्तेमाल को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप 1947 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप hepl@uidai.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं या UIDAI वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

भूलकर भी इन लोगों को नहीं खाना चाहिए चुकंदर, हो सकता है भारी नुकसान

चुकंदर खाना वैसे सेहत के लिए काफी हेल्दी होता है। लेकिन इन लोगों को चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे शरीर को काफी नुकसान होता है। जिन लोगों को किडनी की समस्या और डायबिटीज की समस्या है ऐसे लोगों तो भूलकर भी चुकंदर का सेवन न करें। इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए चुकंदर।

नई दिल्ली। शरीर के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी चुकंदर ही माना जाता है। इसके सेवन से स्वास्थ्य को कई लाभ मिलते हैं। हालांकि, कुछ लोगों के लिए चुकंदर का सेवन करना अभिशाप बन सकता है। इसलिए इसका सेवन करने से पहले जान लें ये बातें। वैसे तो चुकंदर में कई पोषक तत्व पाएं जाते है लेकिन कुछ लोगों के लिए चुंकदर का सेवन या चुकंदर का जूस भूलकर भी नहीं पीना चाहिए। वरना बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आइए जानते हैं किन लोगों को चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए।

किडनी की समस्या

सेहत के लिए चुकंदर काफी हेल्दी होता है लेकिन इसमें अधिक मात्रा में ऑक्सेल्ट पाया जाता है। जो इसके अधिक सेवन से बचना चाहिए। अगर जिन लोगों को किडनी की समस्या है लेकिन चुकंदर खा रहे हैं तो आज ही इसे खाना बंद कर दें। क्योंकि चुकंदर खाने से समस्याएं अधिक बढ़ सकती है।

एलर्जी होने पर

अगर जिन लोगों को स्किन एलर्जी, रैशेज और खुजली की समस्या से परेशान रहते हैं। उन लोगों को चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में इन लोगों को चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए।

प्रेग्नेंट महिलाएं के सेवन न करें

जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन लोगों को चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बीटाइन पाया जाता है। इसका सेवन करना प्रेग्रेंट महिलाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में मां बनने वाली महिलाओं को चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए।

पाचन की समस्या

अगर आपको पाचन की समस्या रहती है तो आपको चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो चुकंदर में अच्छी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। लेकिन इसका अधिक सेवन से कई बार लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

लो ब्लड प्रेशर की समस्या

चुकंदर में सबसे ज्यादा पोटैशियम और सोडियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ऐसे में लो ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान लोगों को इसका सेवन करने बचना चाहिए।

ब्लड शुगर बढ़ने पर

चुकंदर में अधिक मात्रा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है। इसका सेवन करने से शुगर बढ़ जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज से पीड़ित लोगों को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

अगस्त में पार्टनर के साथ तमिलनाडु की इन हसीन जगहों पर पहुंचे, जिंदगी में भर जाएगा रोमांस

दक्षिण भारत देश का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी खूबसूरती देखने के लिए हर दिन हजारों देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको तमिलनाडु की इन शानदार जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए।

दक्षिण भारत देश का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी खूबसूरती देखने के लिए हर दिन हजारों देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में ऐसी कई शानदार और अद्भुत जगहें मौजूद हैं, जहां हर मौसम और हर महीने में घूमने का एक अलग ही मजा होता है। तमिलनाडु में भी ऐसी कई जगहें मौजूद हैं, जहां हर कोई घूमने का सपना देखता है। इस आर्टिकल में हम आपको तमिलनाडु की कुछ शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप अगस्त के महीने में परिवार, दोस्त या पार्टनर के साथ मौज-मस्ती करने के लिए पहुंच सकते हैं।

कोडाइकनाल

अगस्त के महीने में आप तमिलनाडु की सबसे हसीन जगह कोडाइकनाल है। कोडाइकनाल प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद हसीन जगह है। यह जगह समुद्र तल से करीब 7 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन को रूप में जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप यहां पर ब्रायंट पार्क, सिल्वर कैस्केड फॉल्स, कोडाइकनाल झील और कोकर्स वॉक जैसी शानदार जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

वालपराई

तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते होंगे। लेकिन यहां पर स्थित वालपराई हिल्स के बारे में काफी कम लोगों को पता है। बताया जाता है कि इस हिल्स की खूबसूरती कुर्ग, ऊटी और कोडाईकनाल को भी मात देती हैं।

बता दें कि समुद्र तल से करीब 1 हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित वालपराई बेहद शानदार हिल स्टेशन है। अगस्त के महीने में यहां पर पर्यटकों की भारी भीड़ होती है। इस हिल्स को सातवां स्वर्ग भी कहा जाता है। बारिश के मौसम में आपको यहां पर हसीन नजारे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप यहां पर एडवेंचर एक्टिविटी का लुत्फ उठा सकते हैं।

येलागिरी

बेंगलुरु से करीब 3 घंटे की दूरी पर स्थित येलागिरी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यह समुद्र तल से करीब 11 हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसको दक्षिण भारत के टॉप डेस्टिनेशन में आता है। नेचर लवर के लिए यह जगह जन्नत से कम नहीं है।

यह शहर अपनी खूबसूरती के अलावा मनमोहक दृश्यों के लिए भी फेमस है। येलागिरी के सूर्योदय और सूर्यास्त के नजारे पूरे दक्षिण भारत में फेमस हैं। बारिश के मौसम में इस जगह की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। येलागिरी में आप पुंगनूर लेक पार्क, जलगमपराई वॉरफॉल और स्वामीमलाई हिल्स जैसी शानदार जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

वेल्लोर

वेल्लोर दक्षिण भारत का एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। यह तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। पलार नदी के तट पर स्थित वेल्लोर शहर पर विजयनगर, चोलों, राष्ट्रकूट और ब्रिटिश शासकों ने भी हकूमत की है।

यह शहर न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि प्राचीन मंदिरों पर विश्व प्रसिद्ध शैक्षिक और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए भी फेमस है। अगस्त के महीने में यहां पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं।

इन जगहों को करें एक्सप्लोर

आप तमिलनाडु में अन्य कई जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो बेहद शानदार और अद्भुत हैं। आप अगस्त के महीने में सलेम, अनामलाई टाइगर रिजर्व, कन्नूर, चिदंबरम और धनुषकोडी जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

शिक्षक दिवस पर एससी/ एसटी शिक्षको द्वारा बहिष्कार का ऐलान ,प्रधानमंत्री ,राष्ट्रपति को ज्ञापन

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

दिल्ली के अनुसूचित जाति/ जनजाति के हजारों शिक्षको ने संयुक्त अनुसूचित जाति/ जनजाति शिक्षक मंच के आह्वान पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है।

इस बावत शिक्षक मंच के संरक्षक कप्तान सिंह रंगा और संस्थापक एवं सुप्रीमो एनपीपीएस रामकिशन पूनिया ने मीडिया को दिए प्रेस नोट में बताया कि दिल्ली के अनुसूचित जाति/ जनजाति शिक्षको की प्राइमरी से लेकर विश्वविधालय स्तर तक की 41 साल से संघर्षरत एक मात्र यूनियनश्र संयुक्त अनुसूचित जाति / जनजाति शिक्षक मंचश्र दिल्ली की ओर से ऐलान किया गया है कि दिल्ली के अनुसूचित जाति / जनजाति शिक्षक 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का बहिष्कार करेगे।यूनियन सुप्रीमो रामकिशन पूनिया ने आरोप लगाया कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली सरकार के चीफ सेकेट्री को प्रेषित निगम शिक्षा विभाग में आरक्षण घोटाले के 254 से ज्यादा ज्ञापन/रिमाइंडर भेजे जा

चुके है,आखिर विभाग ने वह सब कहां गायब कर दिए। पूनिया के अनुसार इस यूनियन की अपील पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अपनी संवैधानिक शक्तियों.का प्रयोग करते हुए पत्र दिनांकः27.9.2012 ,01.8.2016, 03.8.2017 को तब के तीनो दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर और दिल्ली के चीफ सेकेट्री को आयोग में तलब करके दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग में आरक्षण से संबंधित प्रावधानो के संदर्भ में जो लिखित दिशा निर्देश दिए गए थे उन्हें आज तक भी लागू नहीं किया गया। पूनिया ने बताया कि इस संदर्भ में शिक्षक मंच की ओर से महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को भी दिनांक 20.11.2022 से 23.08.2024 तक करीब 254 से ज्यादा ज्ञापन/ रिमाइंडर लेटर दिए जा चुके है। पूनिया के मुताबिक सभी रिमांडर लैटर को दिल्ली के चीफ सेकेट्री को जिस निर्देश के साथ प्रेषित किये गये, उसे आज तक भी निगम कमिश्नर और दिल्ली के चीफ सेकेट्री ने नही माना है। पूनिया के मुताबिक दरअसल दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग में भारी आरक्षण घोटाला है।

शिक्षक मंच के संरक्षक कप्तान सिंह रंगा एवं एनपीपीएस संस्थापक राम किशन पूनिया ने ऐलान किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर विरोध स्वरूप दिल्ली निगम कमिश्नर के सरकारी आवास पर धरना दिया जाएगा।इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर, महापौर, उप राज्यपाल वीके सक्सेना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पार्लियामेंट कमिटी (एससी/-एसटी,),राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,केंद्रीय सतर्कता आयोग,प्रधानमंत्री,और महामहिम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया जाएगा।

24 वे उन्नत भारत सेवाश्री पुरस्कार के लिए चुना गया एडवोकेट ओ.पी. शर्मा को

सुषमा, नई दिल्ली। हरियाणा के वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट ओ.पी. शर्मा को 24 वें उन्नत भारत सेवाश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें कानूनी सेवाओं और सामाजिक कार्यों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेम्बर एवं हरियाणा-पंजाब बार कौंसिल के पूर्व वाईस चेयरमैन एडवोकेट ओ.पी. शर्मा ने वर्षों से कई महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में अग्रणी भूमिका निभाई है, जहाँ उन्होंने न्याय और समानता के सिद्धांतों की पुरजोर वकालत की है। उन्होंने जरूरतमंद और गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभाई है, जिससे वे अदालत में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सके। उनकी कानूनी सेवाएं केवल अदालत तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सामुदायिक सेवा और कानूनी जागरूकता अभियानों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं, ताकि समाज के हर वर्ग को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हो सके। पुरस्कार समारोह 31 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली के संविधान क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया जाएगा, जहाँ एडवोकेट शर्मा को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। अधिवक्ता ओपी शर्मा का चयन संस्था के हरियाणा सदस्य एवं वरिष्ठ जर्नलिस्ट वैद्य पंडित प्रमोद कौशिक के सुझाव पर संस्था की राष्ट्रीय समिति द्वारा किया गया है।

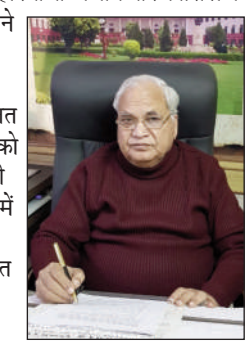

उन्नत भारत संगठन ट्रस्ट के युवा अध्यक्ष अखिल नाथ ने एडवोकेट ओ.पी. शर्मा के चयन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "एडवोकेट शर्मा की कानूनी और सामाजिक सेवाएं समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने विशेष रूप से कमजोर वर्गों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। उन्हें उन्नत भारत सेवाश्री पुरस्कार से सम्मानित करना हमारे लिए गर्व की बात है।"

दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम की बड़ी कार्रवाई, ई-सिगरेट और बटनदार चाकू बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़; 11 गिरफ्तार

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की टीम ने ई-सिगरेट की बिक्री और खरीद में शामिल 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर और गुजरात से अवैध बटन वाले चाकू के चार आपूर्तिकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपितों ने लोगों को अवैध चाकू बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया और देशभर में एक हजार से अधिक लोगों को पिछले आठ महीनों में अवैध चाकू उपलब्ध कराए। पुलिस ने इनके पास से कुल 746 अवैध चाकू बरामद किए हैं।

भारी मात्रा में ई-सिगरेट का भंडारण किया

क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि एएसआई वीरेंद्र, आईएससी क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ लोग दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में अनधिकृत रूप से ई-सिगरेट बेच रहे हैं और आपूर्तिकर्ताओं ने पुरानी दिल्ली के इलाके में भारी मात्रा में ई-सिगरेट का भंडारण किया हुआ है।

तलाशी के बाद कुल 380 पैकेट ई-सिगरेट बरामद

इसके अलावा आपूर्तिकर्ता दिल्ली के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में ऑनलाइन अवैध चाकू की बिक्री में भी लगे हुए हैं। टीम ने पंजाबी बाग क्लब के पास छापेमारी की और दो कारों में 11 लोगों को पकड़ा। तलाशी लेने के बाद कुल 380 पैकेट ई-सिगरेट बरामद किए गए।

आरोपितों की पहचान पश्चिम विहार के विशाल, आयुष मित्तल, करण बग्गा, शिव विहार का गगन मखीजा, मंगोलपुरी का पुनित चंदोक, अमित शौकीन, गुरुग्राम का मनीष बरेरा, नांगलोई का साहिल कौशिक, छतरपुर का चेतन खवादिवा, सुरेश बिश्नोई और राजीव रेलिया के रूप में हुई है।

पांच अलग-अलग प्रकार के 746 अवैध चाकू बरामद

इसके अलावा गोदाम की आगे की तलाशी के दौरान 2330 और ई-सिगरेट के पैकेट और पांच अलग-अलग प्रकार के 746 अवैध चाकू (स्प्रिंग एक्ट्यूएटेड बटनदार चाकू) वाले पांच बक्से भी बरामद किए गए और उन्हें अलग से जब्त कर पुलिस के कब्जे में ले लिया गया और आरोपितों की निशानदेही पर बुराड़ी का राहुल राज, गाजियाबाद का अजय कुमार, सोनीपत का राजीव रेलिया और गुजरात का वरैया धीरज को भी गिरफ्तार कर लिया।

ठेकेदार के हलफनामे से उपराज्यपाल महोदय की चोरी पकड़ी गई है : सौरभ भारद्वाज

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि कुछ दिनों बाद दिल्ली में हर जगह हर न्यूज़ चैनल पर यह चर्चा होने लगेगी, कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का क्या कारण है, इसका जिम्मेदार कौन है ? उन्होंनेp कहा कि दिल्ली और देश में बढ़ते हुए प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है प्रकृति के साथ किया जा रहा बर्बरता पूर्वक बर्ताव I उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के सतबड़ी इलाके में रिज एरिया में गैरकानूनी तरीके से काटे गए 11 00 पेड़ों का मामला चल रहा है और यह पेड़ काटने का काम केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में लाखों की संख्या में भिन्न-भिन्न कारणों से पेड़ों को काटा जा रहा है I उन्होंने कहा कि आज मैं मीडिया के माध्यम से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना जी ने ही गैरकानूनी तरीके से यह 1100 पेड़ कटवाए हैं I उन्होंने कहा कि मैं केवल यह बात हवा में नहीं कह रहा हूं, अब इसके संबंध में कोरे साक्ष्य सामने आ चुके हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी मौजूद हैं I

सतबड़ी रिज एरिया में गैर कानूनी तरीके से काटे गए 1100 पेड़ों के संबंध में डीडीए द्वारा जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उस कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे का जिक्र करते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि डीडीए ने जिस कंपनी को इन 1100 पेड़ों को काटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस कंपनी ने हलफनामे में यह साफ़ तौर पर लिखा है, कि पेड़ों को काटने का आदेश उपराज्यपाल द्वारा दिया गया था I कंपनी द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में लिखी बातें पत्रकारों के साथ साझा करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि इसमें साफ तौर पर कंपनी ने लिखा है कि डीडीए की ओर से यह निर्देश दिए गए थे, कि उनकी ओर से इंजीनियरिंग इंचार्ज मनोज कुमार यादव कंपनी के साथ संपर्क में रहेंगे और जो कोई भी आदेश मनोज कुमार यादव की ओर से दिए जाएंगे वह कंपनी को मानने होंगे I कंपनी ने अपने हलफनामे में बताया कि यह आदेश उन्हें डीडीए की ईमेल आईडी eeswd5@gmail.com के द्वारा मिलते थे I इसी हलफनामे में कंपनी ने यह भी लिखा है, कि उन्हें इस ईमेल आईडी के जरिए पहला ईमेल 7 फरवरी 2024 को प्राप्त हुआ, और दूसरा ईमेल 14 फरवरी 2024 को प्राप्त हुआ I सौरभ भारद्वाज ने बताया कि 14 फरवरी के ईमेल में साफ तौर पर यह बात लिखी गई है कि 3 फरवरी 2024 को उपराज्यपाल महोदय सतबड़ी रिज एरिया में बन रही सड़क का दौरा करने पहुंचे और उन्होंने ही पेड़ों को काटकर जल्द से जल्द सड़क को चौड़ा करने के निर्देश जारी किए I

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे से भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा चुने गए उपराज्यपाल दोनों ही आज आज दिल्ली और देश की जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं I उन्होंने कहा कि इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है, कि जिस कंपनी को पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वह कंपनी अपने हलफनामे में इस बात को बता रही है, कि डीडीए की ओर से ईमेल के जरिए यह आदेश दिए गए कि 3 फरवरी 2024 को उपराज्यपाल महोदय सतबड़ी रिज एरिया का दौरा करने गए और उन्होंने आदेश दिए कि जो भी पेड़ सड़क के चौड़ीकरण में आ रहे हैं उनको काट दिया जाए और सड़क को चौड़ा किया जाए I सौरभ भारद्वाज ने बताया कि यह ईमेल केवल पेड़ काटने वाली कंपनी को ही नहीं बल्कि डीडीए के चीफ इंजीनियर को भी इंजीनियरिंग इंचार्ज द्वारा भेजी गई है।

दिल्ली इतनी असुरक्षित है कि कहीं भी जान जा सकती है: देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नईदिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली इतनी असुरक्षित है कि कहीं भी जान जा सकती है। आप दुकान में बैठे हो कोई गोली मार जाता है, बाहर निकलते हो करंट लगने से मौत हो जाती है, इंस्ट्रीट्यूट में पढ़ते हो वहां भी मरने का डर, घर में हो इमारत गिरने से मौत हो जाती है, नाले में डूबने से मर रहे है। बदहाल प्रशासनिक व्यवस्था और बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण दिल्लीवासी पूरी तरह असुरक्षित है।

यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की विफलताओं के कारण जलभराव से, नालों में डूबने, करंट लगने से और इमारते गिरने, सड़क के गड्ढों आदि में घटी घटनाओं के कारण 35-40 मौते हो चुकी है परंतु आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्री पूरी तरह अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हैं, उन्हें दिल्ली के लोगों के दुखों से कोई सरोकार नही है, कल भी एक बच्चा नाले में गिरने से डूबकर मर गया। उन्होंने कहा कि जेल से बेल पर बाहर आए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जनता के प्रति दायित्व निभाने

की जगह अपनी नौटंकी पदयात्रा करने में व्यस्त है।

यादव ने कहा कि यह दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य है कि बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के अयोग्य राजनीतिक लोग पिछले दस वर्षों से दिल्ली का शासन चला रहे है, जिनमें अधिकतर मंत्रीमंडल के सदस्य, विधायक, पार्षद भ्रष्टाचार के कारण जेल में जा चुके है और भ्रष्टाचार के कारण मुख्यमंत्री तक जेल में है। उन्होंने कहा कि जलजमाव, जलसंकट, बिजली कटौती, वायु और जल प्रदूषण लोगों के लिए अभिशाप जैसे जटिल समस्याओं को निपटाने में पूरी तरह विफल रहे है। दिल्ली की आप सरकार और एमसीडी इन समस्याओं का समाधान करने में बुरी तरह विफल रही हैं।

यादव ने कहा कि दिल्ली में लोग मर रहे है परंतु जहां आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए मुख्यमंत्री को निर्दोष घोषित करने में लगी है वहीं भाजपा दिल्ली नगर निगम चुनाव में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए विपक्षी दलों के पार्षदों को पार्टी में शामिल करने का षड्यंत्र रच रही है। दोनों पार्टियों के नेताओं को मरने वाले लोगों के परिवारजनों से कोई सरोकार नही है, जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा सकारात्मक राजनीति के साथ-साथ दिल्ली में दुखी और लाचार लोगों से पूरी सहानुभूति रखती है।

कड़वाहट और रिश्ते

कड़वाहट तो
सभी रिश्तों में होती हैं.
बस, मोहब्बत की चाशनी,
उसे धागे में पिरोती हैं.
इस ज़न्दिगी में यारों
नज़दीकियों के चक्के,
चलते ही रहना चाहिए.
स्नेह का बंधन और
एक-दूसरे के दु:खों को
सहलाते रहना चाहिए.
कोई कितना भी चाहे,
हमें ख़ुद पर भी ऐतबार
होना ही चाहिए.
जो बिखर जाए,
वो रिश्ते ही नहीं
कौन कहता हैं कि
हम वो फ़रिश्ते नहीं.
क्योंकि कड़वाहट तो
सभी रिश्तों में होती हैं.

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)

दिल्ली की जनता से अपील है कि आप दिल्ली को बर्बाद करने वाले अपने दुश्मनों को पहचानें- संजय सिंह

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने रिज क्षेत्र में अवैध रूप से काटे गए 1100 पेड़ों को लेकर एलजी पर तीखा हमला बोला है। ''आप'' के वरिष्ठ नेता एवं सांसद संजय सिंह का कहना है कि भाजपा के एलजी दिल्ली पर्यावरण के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एलजी साहब को पर्यावरण और दिल्लीवालों की चिंता नहीं हैं, उन्हें तो केवल अरबपतियों के फार्म हाउस की चिंता है। इसीलिए उन्होंने अवैध तरीके से 1100 पेड़ कटवा दिए। सुप्रीम कोर्ट में ठेकेदार ने शपथ पत्र दायर कर बताया है कि एलजी साहब 03 फ़रवरी को मौक़े पर आए थे और 1100 पेड़ काटने के आदेश दिए। संजय सिंह ने कहा कि एलजी साहब के अधीन डीडीए की संस्था यूटीपेक दिल्ली में सड़क बनाने के लिए नक्शे बनाती है। उसके नक्शे में फार्म हाउसों की जमीन लेकर सड़क बनाई जानी थी, लेकिन एलजी साहब ने सड़क बनाने के लिए पेड़ों को ही कटवा दिया। हमारी मांग है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कर सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट रखे जाएं और एलजी साहब समेत सभी जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद संजय सिंह ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर कहा कि भारत में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार या सामाजिक संस्थाएं पर्यावरण को बचाने और प्रकृति को सुरक्षित रखने की चिंता कर रही हैं। इसके लिए पौधारोपण का अभियान बढ़-चढ़ कर चलाया जा रहा है। पेड़ लगाओ-जीवन पाओ। पेड़ हमारे लिए जिंदगी है। भारत समेत पूरी दुनिया यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, भाजपा द्वारा दिल्ली को बर्बाद करने के लिए बैठाए गए एलजी वीके सक्सेना उन वृक्षों को खत्म करने पर लगे हैं, जिनसे हमें जीवन मिलता है। एलजी साहब ने अवैध रूप से 1100 पेड़ कटवा दिए, लेकिन भाजपा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की दिन-रात आलोचना करने वाली भाजपा सुप्रीम कोर्ट मे बार-बार लताड़े जाने के बावजूद एलजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है। इसका मतलब है कि भाजपा दिल्ली की बर्बादी में एलजी के साथ पूरी तरह शामिल हैं।

संजय सिंह ने कहा कि इतने सारे पेड़ ऐसे ही नहीं काटे गए। एलजी साहब के अधीन आने वाली डीडीए की संस्था यूटीपेक दिल्ली के अंदर सड़कों का नक्शा तय करती है कि सड़कें कैसे बनेंगी। यूटीपेक द्वारा बनाए गए सड़कों के नक्शे में था कि फार्म हाउसों की जमीन अधिग्रहित कर सड़क बनाई जाएगी। एलजी और भाजपा बताएं कि फार्म हाउस मालिकों से ऐसी क्या डील हुई कि यूटीपेक के नक्शे को दरकिनार कर फार्म हाउसो की जमीन लेने के बजाय पेड़ कटवाए गए और सड़क बनाई गई। यह बात पूरी दिल्ली जानना चाहती है। यह पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने के साथ ही गंभीर जांच का भी विषय है कि एलजी साहब ने फार्म हाउसों को बचाने के लिए 1100 पेड़ क्यों कटवाए?

संजय सिंह ने कहा कि पेड़ काटने वाली कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर इस बात का खुलासा किया है कि अवैध रूप से 1100 पेड़ काटने के मामले में दिल्ली के एलजी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और पेड़ काटने की जानकारी डीडीए के अधिकारियों को भी थी। कंपनी ने शपथ पत्र में कहा है कि 3 फरवरी 2024 को एलजी साहब मौके पर गए थे और उन्होंने पेड़ काटने का आदेश दिया था। जब वन विभाग के अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी तो एलजी साहब ने ठेकेदार को मौखिक तौर पर अनुमति दी और उसने 1100 पेड़ काट दिए गए। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के बजाय इन सारे तथ्यो को रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इसका संख्या लेना चाहिए और अवैध रूप से पेड़ों को काटने के लिए जिम्मेदार एलजी साहब समेत सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

संजय सिंह ने कहा कि 1100 पेड़ों को काटने की मुख्य वजह केवल फार्म हाउसों को बचाना है। यह फार्म हाउस अरबपतियों के हैं। भाजपा और एलजी साहब अरबपति फार्म हाउस मालिकों के साथ खड़े हैं। उनको दिल्ली के पर्यावरण, दिल्ली के लोगों की कोई चिता नहीं है। 14 फरवरी 2024 का एक ई-मेल है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 3 फरवरी को एलजी साहब ने मौके का दौरा किया था और आरओडब्ल्यू के अंदर आने वाले पेड़ काटने के आदेश दिए थे। इन्होंने 14 फरवरी 2024 से पेड़ों को काटने का काम शुरू किया। ईमेल मे साफ लिखा है कि एलजी साहब मौके पर गए और मौखिक तौर पर पेड़ों को काटने के निर्देश दिए और पेड़ काटे गए। इसकी पूरी जानकारी एलजी साहब और डीडीए को है। एलजी साहब द्वारा पेड़ काटने वाले में आने वाली सारी रूकवाटें दूर की गई। इसलिए 1100 पेड़ों को काटने के लिए सीधे तौर पर भाजपा के एलजी जिम्मेदार हैं। दिल्ली की जनता से कहा कि आप दिल्ली को बर्बाद करने वाले अपने दुश्मनों को पहचानें। ये लोग दिल्ली के पर्यावरण को नष्ट करने और अरबपतियों के साथ मिलकर पेड़ों कटवाने और जिंदगियों को बर्बाद करने वाले लोग हैं।

बिलासपुर फ्लाईओवर का काम बंद होने का विरोध, 108 गांव के लोगों ने की महापंचायत

महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे को होडल कुलाना रोड क्रॉस करता है। यहां पर फ्लाईओवर दो तीन दशक पहले ही बना दिए जाने चाहिए थे लेकिन किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लोगों की दो दशकों की मांग के बाद सरकार ने दस वर्ष पहले इस फ्लाईओवर को बनाने की घोषणा की लेकिन अमल नहीं किया गया।

गुरुग्राम। कई महीनों से बिलासपुर फ्लाईओवर का कार्य बंद होने के विरोध में रविवार को 108 गांवों ने महापंचायत की। यह पंचायत भोड़ा कला बावनी के तत्वावधान में बिलासपुर के मंदिर प्रांगण में बुलाई गई।

महापंचायत में पटौदी के साथ तावडू, सोहना, मानेसर क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेता भी पहुंचे। एसडीएम दर्शन सिंह और विभागीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आगामी आठ सितंबर से पहले पहले दोनों तरफ तीन-तीन सर्विस लाइन बनाकर जाम से निजात दिलाई जाएगी।

समय सीमा के अंदर पूरा होगा फ्लाईओवर का काम

उसके बाद तय समय सीमा के अंदर फ्लाईओवर के कार्य को पूरा कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पिछली कंपनी का टेंडर रद्द कर नई कंपनी को टेंडर देने की बात कही। पंचायत में निर्णय लिया गया कि यदि आठ सितंबर तक कार्य नहीं कराया गया तो बड़ी महापंचायत होगी।

12 करोड़ रुपये की लागत शुरू हुआ था काम

महापंचायत में कहा गया कि फरवरी में करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से वेलकिन कंपनी ने यहां बेसिक स्ट्रक्चर का निर्माण शुरू किया था। अक्टूबर या नवंबर तक काम को पूरा किया जाना था। इस 650 मीटर लंबे फ्लाईओवर को तीन स्पेन में बनाया जाना था ताकि किसी भी तरफ से आने वाले वाहन बिना रुके क्रॉसिंग कर सकें। दोनों तरफ सात-सात मीटर का बेस बनाया जाना था।

पहला स्पेन 20 मीटर, दूसरा 30 मीटर और तीसरा स्पेन भी 20 मीटर का बनना था। सरफेस के लिए सात-सात मीटर चौड़ी सर्विस लाइन अलग से बनाई जानी थी। इसके अलावा दो स्मार्ट व्हीकल अंडरपास (एसवीयूपी) भी बनाए जाने थे, ताकि दिल्ली और जयपुर दोनों तरफ से आने वाले वाहनों का आवागमन बिना रोक-टोक हो सके, लेकिन निर्माण करने वाली कंपनी थोड़ा बहुत काम करके ही अपनी मशीनों को उठाकर ले गई।

21 अगस्त की दोपहर जाम में फंसने के कारण एक व्यक्ति की सही समय पर उपचार नहीं मिलने के चलते मौत हो गई, इससे क्षेत्रवासियों में भारी रोष व्याप्त है।

दिनभर लगा रहता है जाम

लोगों की दो दशकों की मांग के बाद सरकार ने दस वर्ष पहले इस फ्लाईओवर को बनाने की घोषणा की, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। हाईवे पर होडल कुलाना रोड की क्रासिंग भी खत्म कर दी।

पचगांव में आए नितिन गडकरी ने भी इसकी घोषणा की थी तथा अक्टूबर 2024 तक यह बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। परंतु दो वर्ष से प्रारंभ हुआ यह कार्य कछुआ चाल चलता रहा और कार्य बीच में ही रोक दिया गया। बहुत कम चौड़ा सर्विस लेन भी टूटा हुआ है।

इससे यहां पर दिन भर जाम लगा रहता है। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आवागमन करने वाले लोग इस जाम से काफी परेशान होते हैं। इस मार्ग से क्षेत्र के सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी आते जाते हैं, लेकिन किसी को इतनी बड़ी समस्या भी दिखाई नहीं देती है।

महापंचायत में लोगों ने कहा कि एनएचएआइ का यह मार्ग 450 फुट चौड़ा है, लेकिन दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण संकरा हो गया है। मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव ने आकर लोगों की बात सुनी तथा महापंचायत के लोगों ने उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि दिए गए आश्वासन के अनुरूप काम न किया गया तो झाड़सा 360 की महापंचायत बुलाई जाएगी।

ये रखीं मांगें

- प्रशासन अविलंब अवैध कब्जे हटवा कर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के दोनों तरफ चार-चार लेन का सर्विस रोड बनाए
- बिलासपुर चौक के पास ही होडल कुलाना रोड के कट दिए जाएं
- बिलासपुर चौक पर पैदल यात्रियों के लिए फुट ओवरब्रिज बनाया जाए
- फ्लाईओवर का बंद पड़ा निर्माण कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाए
- तावडू रोड पर हमेशा भरे रहने वाले पानी की निकासी की समस्या का तुरंत समाधान किया जाए
- राठीवास मोड पर अंडरपास बनाया जाए

बिमला चौधरी ने राव इंद्रजीत का लिया नाम तो लोगों ने छीना माइक

पंचायत में जैसे ही पूर्व विधायक बिमला चौधरी ने कहा कि वह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से बात कर समस्या का जल्द ही समाधान कराएंगी तो पंचायत में बैठे लोगों ने विरोध करते हुए पूर्व विधायक से माइक छीन लिया। लोगों ने शोर शराबे के साथ इसका प्रतिकर किया। लोगों का कहना था कि राव को खुद यहां आना चाहिए था। वे इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें यहां की यह गंभीर समस्या दिखाई नहीं देती।

ये रहे मौजूद

महापंचायत के अध्यक्ष राजेश चौहान, पूर्व विधायक रामबीर सिंह, पूर्व विधायक बिमला चौधरी, पटौदी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष चंद्रभान सहगल, कांग्रेस नेत्री पर्ल चौधरी, पूर्व सेशन जज राम निवास भारती, हुकम चंद पुनिया, सरपंच एकता मंच के जिला अध्यक्ष अजीतसिंह, सुधीर चौधरी, सुखबीर तंवर, पवन चौधरी, पहलवान दिलीप सिंह छिल्लर, नरेंद्र पहाड़ी, सरपंच मनबीर चौहान, पूर्व सरपंच यजुवेंद्र गोगली, महेश सैनी, लक्ष्मी नारायण, हेलीमंडी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शिवकुमार गुप्ता, सरपंच धर्मपाल लोकरी, अमन चौधरी, श्याम बीर चौहान, रमेश गर्ग, सुनीता वर्मा, दीप चंद, सतबीर पहलवान, अजीत ठाकरान, राजेश बिलासपुर, तावडू 84 के प्रधान शिवदत्त सहरावत, हैफेड चेयरमैन राजेश सहरावत उर्फ रज्जू, बिलासपुर सरपंच राजवीर, अजीत सिंह, सोनू गौतम, विनोद शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसायटी के निवासियों का 'हल्लाबोल', बिल्डर के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्थित पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसायटी में रहने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। यहां रह रहे लोगों ने आरोप लगाया कि बिल्डर द्वारा सुविधा में कटौती हो रही है। सोसाइटी में चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि खेल के मैदान बनाने की जगह बिल्डिंग बना दी गई है।

ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर साइट सी स्थित पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसायटी के निवासी बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। शनिवार रात निवासियों ने भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के पदाधिकारियों के साथ बिल्डर के खिलाफ पैदल मार्च भी निकाला।

कई बार की शिकायत लेकिन नहीं हुई सुनवाई-सोसायटीवासी

इस दौरान पुलिस (Greater Noida Police) भी मौजूद रही। निवासियों का आरोप है कि सुविधाओं में कटौती की जा रही है। बिल्डर अवैध निर्माण करा रहा है, सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं है, चोरी की घटनाएं हो रही हैं। कई बार शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के किसान नेता बलराज भाटी ने बताया कि पैरामाउंट गोल्फ फारेस्ट सोसायटी के निवासी बिल्डर प्रबंधन की मनमानी के कारण कई वर्षों से परेशान है। निवासियों ने संगठन से संपर्क करअपनी समस्याओं को रखा। संगठन ने निवासियों के साथ मिलकर बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। उधर निवासी बिल्डर के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं।

सोसायटी में चरमरा हुई सुरक्षा व्यवस्था

निवासियों का आरोप है कि सोसायटी में खेल के मैदान बनाने की जगह बिल्डर ने उस पर अवैध निर्माण कर दिया है। पाथवे पर अवैध तरीके से दुकान बना दी है। इन्हें बिल्डर बेच कर मोटी कमाई कर रहा है। सोसायटी में सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। आए दिन चोरी की घटनाएं होती है। मांग की कि सुरक्षा के लिए दूसरी एजेंसी को काम दिया जाए।

परिसर में करीब दो हजार परिवार रहते हैं। हर महीने करोड़ों रुपये का मेंटेनेंस निवासियों से वसूला जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। इस बार में बिल्डर के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नहीं। उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

5 से 12 सितंबर तक दाखिल होंगे नामांकन, प्रचार में 40 लाख खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2024 की नामांकन प्रक्रिया पांच से 12 सितंबर तक चलेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक पार्टियां तथा उम्मीदवार आपस में सौहार्द का वातावरण बनाए रखेंगे। चुनाव संपन्न होने तक कहीं भी तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। एक प्रत्याशी प्रचार में 40 लाख रुपये खर्च कर सकेगा।

गुरुग्राम। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की तैयारी जिला प्रशासन ने तेज कर दी है। पांच सितंबर से गुड़गांव, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना के एसडीएम कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं।

नामांकन करने के दौरान उम्मीदवार के साथ चार से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2024 की नामांकन प्रक्रिया पांच से 12 सितंबर तक जारी रहेगी। रविवार आठ सितंबर को नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के नियम अनुसार उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष अनिवार्य है।

मतदाता सूची में नाम होना जरूरी

साथ ही उम्मीदवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। प्रदेश की किसी भी विधानसभा मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है। उम्मीदवार अगर पंजीकृत पार्टी का है तो उसके लिए एक मतदाता प्रस्तावक होगा।

निर्दलीय व गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार के साथ 10 प्रस्तावक होने चाहिए। उम्मीदवार किसी दूसरे जिले से आकर यहां चुनाव के लिए फार्म भरता है तो वह अपनी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करवा कर लाएगा।

नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार को अपनी तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र की प्रति, चुनाव के लिए खुलवाए गए नए बैंक अकाउंट की कॉपी और एक एफिडेविट देना होगा, जिसे फॉर्म 26 कहा जाता है। इस शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी चल-अचल संपत्ति, लोन, देनदारी, अपराधिक रिकॉर्ड का पूर्ण विवरण देना है।

उम्मीदवार अपने बैंक अकाउंट से करेगा सारा खर्च

नामांकन के समय उम्मीदवार सहित पांच लोग ही रिटर्निंग ऑफिसर कम एसडीएम की कोर्ट परिसर में मौजूद होने चाहिए। एसडीएम कार्यालय से 100 मीटर की दूरी में उम्मीदवार तीन से अधिक वाहन नहीं ला सकता। उम्मीदवार अपने नए बैंक अकाउंट से चुनाव का सारा लेन-देन का कार्य करेगा।

चुनाव का हिसाब-किताब रखने के लिए एक खर्चा रजिस्टर उम्मीदवार के पास व एक निर्वाचन कार्यालय में रखा जाएगा। एक प्रत्याशी 40 लाख रुपये इस चुनाव में खर्च कर सकता है। नामांकन के लिए सामान्य उम्मीदवार को 10 हजार रुपये और अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवार को पांच हजार रुपये की फीस जमा करवानी होगी।

रोड शो में केवल चुनाव प्रचार हो: निशांत यादव

निशांत यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक अहम कड़ी है। यह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना चाहिए, जिससे कि हमारे इलाके व प्रदेश की साफ-सुथरी छवि बनी रहे। चुनाव में किसी बात को लेकर आपस में क्लेश पैदा नहीं होना चाहिए।

खासतौर से जनसभा या रोड शो के समय दूसरी पार्टी या प्रत्याशी के कार्यकर्ता विघ्न न डालें। रोड शो के लिए आवेदन करते समय जो रूट प्रशासन को बताया जाएगा, उसे अनुमति मिलने के पश्चात परिवर्तित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि एक पार्टी अपना रोड शो निकाल रही है और उनका भी वही रूट है तो दो-तीन घंटे बाद वहां से गुजरें।

रोड शो की वजह से बाधित न हो यातायात

रोड शो में केवल चुनाव प्रचार किया जा सकता है, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रोड शो की वजह से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। चुनाव के हर कार्य को पूरा करवाने में राजनीतिक दल सरकारी अधिकारियों का सहयोग करेंगे। चुनाव के काम में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। जिला प्रशासन का सभी पार्टियों व उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार रहेगा।

जनसभा का स्थान पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार जनसभा का आयोजन नहीं करेगा। प्रचार में किसी प्रकार के अनुचित संसाधनों जैसे नशीले पदार्थ, नकदी आदि का प्रयोग न करें और न ही मतदाता पर वोट का दबाव डालें।

नारी स्वतंत्रता के सबसे बड़े पैरोकार श्री कृष्ण

परिवहन विषेश

पूरा देश श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव में डूबा हुआ है। लेकिन क्या यह उत्सव ही श्री कृष्ण को समझने की कोशिश का एक मात्र मार्ग और लक्ष्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में श्री कृष्ण की भक्ति के साथ उनकी वाणी भगवद् गीता की महिमा भी बढ़ती जा रही...

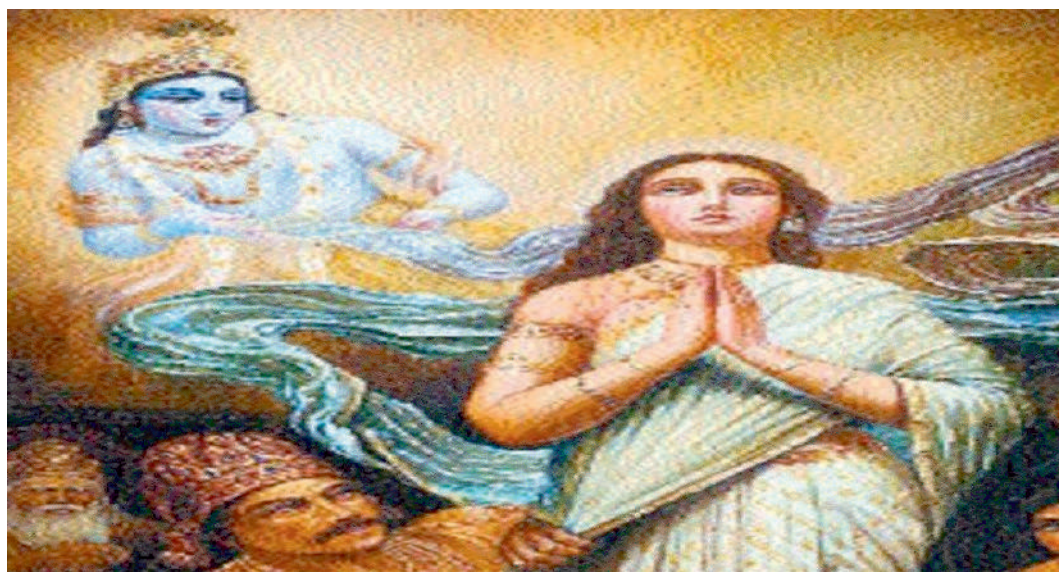

पूरा देश श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव में डूबा हुआ है। लेकिन क्या यह उत्सव ही श्री कृष्ण को समझने की कोशिश का एक मात्र मार्ग और लक्ष्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में श्री कृष्ण की भक्ति के साथ उनकी वाणी भगवद् गीता की महिमा भी बढ़ती जा रही है। यह सुखद है लेकिन इस अत्याधुनिक दौर की दुनिया में क्या श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण हो पा रहा है। आज के संदर्भ में श्री कृष्ण का मार्ग सबसे ज्यादा अनुकरणीय है।

समाज में पाखंड बढ़ता जा रहा है। नारी स्वतंत्रता कहीं ज्यादा खतरे में है। दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और शांति के नाम पर भेदभाव हो रहा है। पर्यावरण खतरे में है और तंत्र-मंत्र जादू-टोना करने वाले फल फूल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होते ही पहले ब्रज याद आता है और फिर महाभारत काल। ब्रज की भूमि में वह प्रेम के पुजारी हैं। वह उस ब्रज रज में लौटते हैं जहां आज भी बार-बार यह विश्वास होता है यहीं तो हैं श्री कृष्ण। ऐसी-ऐसी लीलाएं जिस पर संत और दुनिया भर से आने वाले भक्त न्यौछावर हैं। ऐसी दीवानगी कि रसखान ब्रज के ही हो गए। लेकिन ज्यों ही श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर बाहर जाते हैं वह योगेश्वर श्री कृष्ण हो जाते हैं। वह अपने सखा अर्जुन को बीच कुरुक्षेत्र में उपदेश देते हैं और कहते हैं -

हे अर्जुन ! जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं। श्री कृष्ण का स्मरण होते ही पहले ब्रज याद आता है और फिर महाभारत काल भी। वास्तव में ऐसे अलौकिक और अद्वितीय चरित्र दुनिया में कम ही देखने को मिलते हैं जैसा भगवान श्री कृष्ण का है। वह बाल गोपाल है। उनके नाम संकीर्तन पर नृत्य करते हैं झूमते हैं। रसखान भी उन पर न्यौछावर हो जाना चाहते हैं और सूरदास भी। उनका पूरा जीवन चरित्र रूढियों को तोड़ता है। अंधविश्वासों को खत्म करता है। पाखंड को धिक्कारता है। पूरे ब्रजवासी जब इंद्र की पूजा की तैयारी में व्यस्त थे तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि किसकी पूजा कर रहे हो।

इंद्र देवता हैं इसलिए क्या उनकी पूजा उचित है। हम सब प्रकृति की पूजा क्यों नहीं करते। हम गाय की पूजा क्यों नहीं करते जो जीवन दायिनी है और उन्होंने इंद्र की जगह गिरीराज जी का पूजन कराया। इंद्र के स्थान पर गाय की पूजा हुई। विडंबना तो देखिए महाभारत टालने के प्रयास में श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के धृतराष्ट्र के दरबार में चले जाते हैं और यह प्रस्ताव देते हैं कि शांति के लिए पांडव सिर्फ 5 गांव लेकर मान जाएंगे। क्या शांति का इससे बड़ा प्रस्ताव कभी दुनिया में देखा गया है। शायद नहीं लेकिन जब शांति की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं और कौरव और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने-सामने खड़ी हो जाती हैं तब अर्जुन को मोह पैदा होता है। अपने परिवार के प्रति मोह के कारण ही वह शांति की बात करने लगते हैं लेकिन श्री कृष्ण इस प्रस्ताव को नहीं मानते और अर्जुन के शांति प्रस्ताव को कायरता बताते हैं। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की यही विराटता है कि वह देशकाल परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय करते हैं। वह शांति के पुजारी हैं लेकिन जो लोग शांति के मार्ग में बाधक हैं उनको दंड भी दिलाना वह जानते हैं।

श्री कृष्ण नारी स्वतंत्रता के सबसे बड़े पैरोकार हैं। द्रौपदी उनके लिए नारी स्वतंत्रता की प्रतीक है जिसका भरी सभा में चीर हरण कर अपमान करने की कोशिश की गई। भीष्म पितामह उनके प्रिय हैं लेकिन जब रणभूमि में पितामह को सामने देख पितामह पर तीर चलाने में अर्जुन के हाथ कांपते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें याद दिला देते हैं जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हो रहा था तब पितामह शांत बैठे थे। चुपचाप बैठे थे। नारी के अपमान पर चुपचाप बैठे पितामह उतने ही दोषी हैं जितना अपमान करने वाले। सुभद्रा का विवाह जबरन दुर्योधन से कराया जा रहा था लेकिन सुभद्रा की इच्छा जानकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह सुभद्रा को ले जाएं। श्री कृष्ण के इस निर्णय पर तमाम सवाल उठते हैं लेकिन श्री कृष्ण का एक जवाब था कि नारी की इच्छा के बिना परिवार उसका किसी से भी विवाह नहीं करा सकता। श्री कृष्ण का पूरा जीवन चुनौतियों और संघर्षों से भरा है। यह इसलिए क्योंकि वह पूरे समाज को यह सीख देना चाहते थे कि चुनौतियां कितनी ही बड़ी क्यों न हो शांत बैठने वाले कायर होते हैं।

गुजरात में समुद्र तट पर पहुंचकर द्वारिका नगरी बसाते हैं लेकिन द्वारिका में चैन से बैठ भी पाते कि महाभारत के युद्ध की आहट आने लगती है। वह शांति दूत बन हस्तिनापुर जाते हैं। हरसंभव प्रयास करते हैं कि महाभारत को रोका जाए लेकिन जब नहीं रुकता और वह अर्जुन के सारथी बनते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होता है और लौटकर द्वारिका में कुछ दिन भी चैन से नहीं बैठ पाते कि उनके परिवार में ही कलह शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। वह सतत संघर्ष करते रहे, समाज को नई राह दिखाते रहे। वह सबसे बड़े उपदेशक हैं उस सत्य की राह के जिससे लोग भटक गए हैं।

विकसित भारत के संकल्प को पूरा होने से रोकने के लिए रची गयी है एक बड़ी साजिश

सिर्फ मोबाइल पर ही अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है, आप तमाम प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध वेब सीरिजों को देख लीजिये। अधिकतर में द्विअर्थी संवाद और अश्लील दृश्य भरे पड़े हैं। यही नहीं, हिंदी सिनेमा की भी कुछेक ही फिल्में ऐसी आती हैं जिन्हें परिवार के साथ देखा जा सकता है।

भारत जब विकसित देश बनने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है तो उसकी राह में बाधाएं पैदा करने के लिए तमाम तरह की साजिशें की जा रही हैं। इनमें से एक साजिश है देश के युवाओं को नशे और अश्लीलता के दुष्चक्र में फंसाने की और यह साजिश काफी हद तक सफल होती भी दिख रही है। कॉलेजों के आसपास आसानी से मादक पदार्थ मिल जाते हैं, रेव पार्टियों का चलन देश में बढ़ चुका है, मोबाइल पर अश्लील कंटेंट आसानी से उपलब्ध है। इस सबसे युवाओं के दिलो-दिमाग पर बड़ा असर पड़ रहा है और वह अपनी असल जिम्मेदारियों से विमुख होकर भ्रमित हो रहे हैं। विकसित भारत के लिए आज जो आधार तैयार किया जा रहा है उस पर इमारत युवाओं को ही आगे चलकर खड़ी करनी है इसलिए सरकार को चाहिए कि वह युवाओं के जीवन और देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।

वैसे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल पर ही अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है, आप तमाम प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध वेब सीरीजों को देख लीजिये। अधिकतर में द्विअर्थी संवाद और अश्लील दृश्य भरे पड़े हैं। यही नहीं, हिंदी सिनेमा की भी कुछेक ही फिल्में ऐसी आती हैं जिन्हें परिवार के साथ देखा जा सकता है। हर जगह पसरी इस अश्लीलता का बाल मन पर बड़ा असर पड़ रहा है। इसके चलते बाल्यकाल में ही छात्र गालियां सीख जा रहे हैं साथ ही अश्लील कंटेंट उन्हें गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है जिसके चलते किशोरवय उम्र में ही शारीरिक संबंध बनाने या दुष्कर्म करने की खबरें आम हो रही हैं। खास बात यह है कि इस सब पर माता-पिता भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह खुद मोबाइल में व्यस्त हैं।

बहरहाल, इन सब स्थितियों से निकलने के लिए किसी से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। समय आ गया है जब हम आत्मचिंतन करें और देखें कि हमारा परिवार, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? समय आ गया है कि हम चिंतन करें कि देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का जो लक्ष्य रखा है उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है? निश्चित ही आत्ममंथन से निकलने वाला अमृत देश के लिए और हमारे अपने लिये भी हितकारी होगा।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

एमजी विंडसर ईवी ने कच्छ के रण में दिखाया अपना दम

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जेएसडब्लू एमजी मोटर्स अपनी नई गाड़ी विंडसर ईवी लॉन्च करने जा रही है। इसे बाजार में उतारने से पहले कंपनी कई स्तरों पर इसकी टेस्टिंग कर रही है। इस बार कंपनी ने इस गाड़ी का तीसरा टीजर जारी किया है।

कंपनी की ओर से गाड़ी का तीसरा टीजर जारी किया गया है। इस नए टीजर में दिख रहा है कि कंपनी कच्छ के रण में गाड़ी की टेस्टिंग कर रही है। जहां तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच रहता है। इससे पहले कंपनी ने गाड़ी को लेह के पहाड़ों और उदयपुर में वाटर वेडिंग टेस्ट में भी चलाया था।

कंपनी ने एमजी विंडसर ईवी में कई एडवांस फीचर्स जोड़े हैं, जैसे कि कार में आपको 15.6 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और 8.8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर दूसरे फीचर्स पर नजर डालें तो आपको वायरलेस फोन चार्जर, पावर्ड बूट लिड, सिक्स-स्पीकर साउंड सिस्टम, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे।

ईवी वाहनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज इसकी बैटरी है। इस वाहन में आपको 50.6kwh की बैटरी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 460 किलोमीटर की रेंज देगी।

एमजी मोटर इंडिया अपनी विंडसर ईवी को 11 सितंबर 2024 को लॉन्च करेगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। बाजार में आने के बाद इसका सीधा मुकाबला नेक्सन ईवी, कर्व ईवी जैसी गाड़ियों से होगा।

रायपुर में 5 फास्ट चार्जिंग ईवी स्टेशन किए जाएंगे स्थापित, नगर निगम आईओसी के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम यानी आरएमसी शहर में दस फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है। यह प्रोजेक्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से किया जाएगा। इसके साथ ही आरएमसी देश का पहला नगर निकाय बन जाएगा, जो किसी पीएसयू के साथ इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है।

इस परियोजना से शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम होगा। पहले चरण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम परिसर, गांधी उद्यान, आउटडोर स्टेडियम परिसर में स्थित पुराने स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय परिसर, सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने अनुपम गार्डन और जवाहर बाजार पार्किंग में फास्ट फोर व्हीलर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।

आरएमसी कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने कहा कि हम पीएसयू के साथ फ़ास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले देश के पहले नगर निकाय हैं। पहले चरण में पांच स्टेशनों पर काम शुरू हो गया है। शेष पांच चार्जिंग स्टेशन दूसरे चरण में बनाए जाएंगे। रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर नगर आयुक्त अविनाश मिश्रा और कार्यकारी अभियंता इमरान खान ने प्रस्तावित फ़ास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशनों की समीक्षा के लिए साइट निरीक्षण किया। जनहित में आवश्यक विचार-विमर्श के बाद नगर आयुक्त ने परियोजना को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

राजधानी में चार जगहों पर फास्ट फोर व्हीलर ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू हैं। ये स्टेशन नगर निगम मुख्यालय पार्किंग क्षेत्र, भटगांव स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट के सामने मल्टीलेवल पार्किंग और जयस्तंभ चौक के पास पुराने बस स्टैंड मल्टीलेवल पार्किंग में चालू हैं। इन स्टेशनों की स्थापना आरएमसी ने ही की है।

अप्रैल से जुलाई 2024 तक इन ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर कुल 3499.17 यूनिट बिजली की खपत हुई है। इन स्टेशनों से लगभग 10.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से राजस्व प्राप्त होता है। इससे रायपुर नगर निगम को अच्छी आय होती है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर बिजली की खपत में हर महीने लगभग 30% की वृद्धि हुई है, जो नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और उत्साहजनक रुझान को दर्शाता है।

कार्यकारी अभियंता ने बताया कि अप्रैल 2024 में चारों ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर 378.83 यूनिट बिजली की खपत हुई। मई 2024 में खपत 701.24 यूनिट थी। जून 2024 में यह 1050.10 यूनिट और जुलाई 2024 में यह 1369 यूनिट तक पहुंच गई। अप्रैल से जुलाई 2024 तक चार महीनों में इन चार ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर कुल बिजली की खपत 3499.17 यूनिट थी। यह पहल टाटा और एथर पावर जैसी कंपनियों की साझेदारी में की जा रही है। इससे शहर भर में विभिन्न स्थानों पर वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग संभव हो सकेगी।

ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन नही ले रहा रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स

परिवहन विशेष न्यूज

25 अगस्त को फेडरेशन ऑफ सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ द्वारा ई-मोबिलिटी और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर सेक्टर 35 स्थित एक निजी होटल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में फॉसवेक के अलावा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने भी भाग लिया।

बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए क्रेस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक, पर्यावरण विभाग, चंडीगढ़ नवनीत कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 15 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है।

उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करके भारत के ऊर्जा परिदृश्य को बदलना है। यह महत्वाकांक्षी योजना घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने की लागत के चालीस प्रतिशत तक सब्सिडी देकर सौर ऊर्जा के उपयोग को सक्षम बनाती है। उन्होंने आगे कहा कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन पांच साल के लिए कोई पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स नहीं ले रहा है, जबकि पारंपरिक ईंधन पर चलने वाले वाहनों के मालिकों को दोनों का भुगतान करना होगा।

बुलंदशहर जिले में चलेंगी इलेक्ट्रिक बस, दिसंबर तक बस चलाने पर दिया जा रहा जोर

परिवहन विशेष न्यूज

बुलंदशहर जिले की सड़कों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने वाली हैं। इलेक्ट्रिक बसें चलने पर आम लोग इसमें सफर कर सकेंगे। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को निजात दिलाने के लिए दिसंबर तक बस का संचालन शुरू करने को लेकर परिवहन अफसर तैयारियों में जुट गए हैं।

एआरटीओ प्रवर्तन राजीव बंसल ने बताया कि वीडियो कॉफ्रेंस में उच्च अफसरों ने टैक्स जमा करने और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कराने को लेकर निर्देश दिए। बताया कि जिले के बड़े स्कूल-कॉलेज और बड़े प्रतिष्ठान-कंपनी में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए जागरूक किया जाएगा। जिससे संबंधित अपने यहां पर डीजल-सीएनजी की जगह इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करा सकें।

इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से जिले में पर्यावरण प्रदूषण पर भी काफी हद तक लगाम लगेगी। जिले में दिसंबर माह से पूर्व इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करवाने के लिए प्रयास रहेगा।

चीन से आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाएगा कनाडा

परिवहन विशेष न्यूज। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार, 26 अगस्त को यह ऐलान भी किया कि चीन से इस्पात और एल्युमीनियम के आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। ट्रूडो ने नोवा स्कोटिया के हैलिफैक्स में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ''चीन जैसे देशों ने वैश्विक बाजार में खुद को अनुचित लाभ देने का विकल्प चुना है।'' ट्रूडो की सरकार ने इस गर्मी की शुरुआत में इस मुद्दे पर 30-एल दिन का परामर्श शुरू किया था। कनाडा का यह कदम अमेरिका और यूरोपीय आयोग दोनों द्वारा चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर ऊंचा आयात शुल्क लगाने की योजना की घोषणा के कुछ सप्ताह बाद आया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने रविवार को नोवा स्कोटिया के हैलिफैक्स में ट्रूडो और कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक के दौरान कनाडा को इस तरह का कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था। अभी कनाडा में चीन निर्मित एकमात्र ईवी टेस्ला का आयात हो रहा है जो कंपनी के शंघाई कारखाने में बने हैं। फिलहाल कोई चीनी ब्रांड वाला इलेक्ट्रिक वाहन कनाडा में बेचा या आयात नहीं किया जा रहा है। कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि कनाडा इस मामले में अमेरिका और यूरोपीय संघ में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा क्योंकि उत्तरी अमेरिका में एक एकीकृत वाहन क्षेत्र है।

क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कनाडा चीन की अत्यधिक आपूर्ति के लिए 'डंपिंग' स्थल न बने।

सी-डैक ने विद्युत गुणवत्ता समाधान की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और विभिन्न उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन/एमओए पर हस्ताक्षर के साथ मॉडल ईवी चार्जिंग स्टेशन और हार्डवेयर इम्यूलेशन सुविधा का किया उद्घाटन

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव श्री एस कृष्णन ने सी-डैक तिरुवनंतपुरम, टेक्नोपार्क परिसर में मॉडल स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस केंद्र में 2W से लेकर भारी वाहनों तक के वाहनों के लिए विभिन्न AC और DC फास्ट चार्जर होंगे और उद्योगों के माध्यम से स्वदेशी EV चार्जर अनुसंधान, विकास, व्यावसायीकरण और विनिर्माण के साथ चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इसके अलावा, MeitY के सचिव ने आज सी-डैक, तिरुवनंतपुरम में सी2एस कार्यक्रम और MeitY की DLI योजना के तहत स्टार्ट-अप के लिए हार्डवेयर इम्यूलेशन सुविधा का भी उद्घाटन किया। इस केंद्र में वीएलएसआई और एसओसी प्रौद्योगिकियों के लिए हार्डवेयर डिजाइनों का विकास, परीक्षण और सत्यापन किया जाएगा। यह सुविधा एफपीजीए जैसे पुनः विन्यास योग्य प्लेटफार्मों पर हार्डवेयर डिजाइनों के अनुकरण के लिए संसाधन प्रदान करती है।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री एस. कृष्णन ने कहा, "औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए भारत में बौद्धिक संपदा का सृजन करना यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत आगे रहे। सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय समाधान पेश करने का लक्ष्य रखा है। इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों और समाधानों का विकास स्वदेशीकरण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"

इन उद्घाटनों के साथ-साथ, आज सी-डैक, तिरुवनंतपुरम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की उपस्थिति में उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, समझौता ज्ञापन/एमओए और उत्पाद लॉन्च के लिए अन्य घोषणाएं की गईं। विवरण इस प्रकार हैं:

सी-डैक (टी) और आईआईएससी, बैंगलोर द्वारा विकसित उच्च वोल्टेज उच्च आवृत्ति प्लानर मैग्नेटिक्स प्रौद्योगिकी की प्रौद्योगिकी का मेसर्स रेलियामोटिव लैब्स, बैंगलोर को हस्तांतरण: यह 10kV तक के निम्न, मध्यम या उच्च वोल्टेज और 200 kHz तक की उच्च आवृत्तियों वाले किसी भी अनुप्रयोग के लिए वांछित रेटिंग के साथ किसी भी प्लानर इंडक्टर को डिजाइन और परीक्षण करने में सक्षम है। 200 kHz तक की आवृत्तियों के साथ 10kV तक की सीमा वाले विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्लानर ट्रांसफॉर्मर का डिजाइन और परीक्षण।

विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए वीईजीए प्रोसेसर-आधारित एसओसी के विकास के लिए सी-डैक (टी) और मेसर्स एलएंडटी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सी-डैक रक्षक और दर्पण वर्चुअल नेटवर्क सॉल्यूशंस जैसे नेटवर्क सुरक्षा समाधानों के विकास के लिए सी-डैक (टी), सी-डैक, चेन्नई और मेसर्स अहीसा डिजिटल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सी-डैक रक्षक स्वदेशी बॉस ओएस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, इसमें एक नेटवर्क फोरेंसिक पोर्टल एप्लिकेशन शामिल है जिसमें स्वदेशी एआई एल्गोरिदम और सी-डैक क्लाउड पर चलने वाले कस्टम इंजन शामिल हैं, जो उल्लंघनों का पता लगाने और साइबर फोरेंसिक के लिए व्यापक समर्थन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। दर्पण वर्चुअल नेटवर्क सॉल्यूशन 'एसडीएन आधारित एज प्लेटफॉर्म के लिए नेटवर्क सॉफ्टवेयराइजेशन का एक उत्पाद है जो रूटिंग, स्विचिंग और फ़ायरवॉलिंग जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर-आधारित नेटवर्क फ़ंक्शन की तैनाती का समर्थन करता है।

वाहन से ग्रिड (V2G, V2H और V2B) प्रौद्योगिकियों के विकास और कार्यान्वयन के लिए हाइकॉन इंडिया लिमिटेड और सी-डैक (T) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। V2G की पहचान ऐसी प्रौद्योगिकी के रूप में की गई है जो लोड कर्व को समतल करने, परस्पर जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भंडारण समाधान और टिकाऊ इलेक्ट्रिक ड्राइव परिवहन में ग्रिड सहायता प्रदान करने के लिए पावर और परिवहन को जोड़ती है। वाहन से ग्रिड (V2G), वाहन से घर (V2H) और वाहन से भवन (V2B) की प्रौद्योगिकी का विकास NaMPET के तहत किया गया है।

उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) के लिए स्मार्ट मीटर प्रौद्योगिकियों के विकास, परिनियोजन और प्रसार के लिए सी-डैक (टी) और मेसर्स जेएमवी एलपीएस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए:। सीडैक ने एनएएमपीईटी के सहयोग से उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) प्रौद्योगिकी भी विकसित की है, जो स्मार्ट मीटरिंग प्रौद्योगिकी के अगले विकास का प्रतिनिधित्व करती है। यह पारंपरिक स्मार्ट मीटर की बुनियादी कार्यक्षमताओं से आगे बढ़कर अधिक परिष्कृत और परस्पर जुड़े समाधान प्रदान करता है।

हाइकॉन इंडिया लिमिटेड द्वारा माइक्रोग्रिड प्रौद्योगिकियों के लिए हाइब्रिड पावर कंडीशनिंग सिस्टम का उत्पाद लॉन्च। कोच्चि को सी-डैक (टी) के साथ विकसित किया गया है। लचीले औद्योगिक माइक्रोग्रिड के लिए हाइब्रिड पावर कंडीशनिंग सिस्टम को NaMPET कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। डिजाइन और नियंत्रण के माध्यम से अतिरेक और दोष सहिष्णुता सुनिश्चित करके लचीलापन हासिल किया गया है। पावर कन्वर्टर्स के लिए मजबूत हार्डवेयर और उन्नत शीतलन प्रणाली को भी डिजाइन में संबोधित किया गया है। नियंत्रण प्रणाली ग्रिड सिंक्रनाइज़ेशन और स्थिरता सुनिश्चित करती है। डिजिटल नियंत्रण प्लेटफ़ॉर्म में डायग्नोस्टिक्स को लागू करने के लिए संसाधन भी प्रदान किए गए हैं।

उद्घाटन, ToT, समझौता ज्ञापन/MoA सी-डैक तिरुवनंतपुरम में श्री एस कृष्णन, सचिव, MeitY; श्री एस के मारवाह, समूह समन्वयक, MeitY; श्री ई मगेश, महानिदेशक, सी-डैक; श्री कलाई सेल्वन, निदेशक सी-डैक-टी; डॉ ओम कृष्ण सिंह, वैज्ञानिक 'डी', MeitY; श्री संदीप कुमार, सीईओ एल एंड टी सेमीकंडक्टर्स; श्री संजय गुप्ता, सीडीओ और एल एंड टी सेमीकंडक्टर्स के वैश्विक इंजीनियरिंग प्रमुख; श्री श्रीधरन मणि संस्थापक और निदेशक, अहीसा डिजिटल इनोवेशन; श्री क्रिस्टो जॉर्ज, एमडी, मेसर्स हाइकॉन प्राइवेट लिमिटेड; श्री सदीप शशिधरन, निदेशक, मेसर्स रेलियामोटिव प्राइवेट लिमिटेड; श्रीमती मीनाक्षी सिंह, निदेशक मेसर्स जेएमवी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य उद्योग भागीदारों की उपस्थिति में किया गया।

खाद्य कीमतों पर सतर्कता जरूरी

डा. जयंती लाल भंडारी

हाल ही में 22 अगस्त को वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2024 में दक्षिण पश्चिमी मानसून में प्रगति के कारण खरीफ की बोआई अच्छी हुई है और खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में और कमी आ सकती है।

हम उम्मीद करें कि अगस्त 2024 में जिस तरह खुदरा उपभोक्ता महंगाई रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित चार फीसदी के लक्ष्य से भी कम है, उसी तरह सरकार भविष्य में भी खुदरा महंगाई दर को नियंत्रित रखने के लिए प्रयास करेगी व नए दाम स्थिरीकरण कोष तथा खाद्य भंडारण व वेयरहाउसिंग के लिए किए गए बजट आवंटनों के उपयोग पर शुरुआत से ध्यान देगी'

हाल ही में 22 अगस्त को वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2024 में दक्षिण पश्चिमी मानसून में प्रगति के कारण खरीफ की बोआई अच्छी हुई है और खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में और कमी आ सकती है। इसी तरह पिछले दिनों 19 अगस्त को रिजर्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि यद्यपि देश में बेहतर मानसून, अच्छे मौद्रिक प्रबंधन और सरकार के द्वारा तत्परता से महंगाई नियंत्रण के उपायों से महंगाई घटने का सुकूनदेह परिदृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी खाद्य कीमतों पर सतर्कता जरूरी है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि महंगाई सरकार की चिंता बनी रही है और अब सरकार ने संकेत दिया है कि महंगाई नियंत्रण के लिए बहुआयामी रणनीति की डगर पर आगे बढ़ती रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के बजट के तहत शीघ्र खराब होने वाले सामान की बाजार में समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। बजट के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग को दाम स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के लिए 10000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जहां इस कोष का उपयोग दाल, प्याज और आलू के बफर स्टॉक को रखने के लिए किया जाएगा, वहीं जरूरी होने पर इन अन्य खाद्य वस्तुओं के बढ़े दामों को नियंत्रित करने के लिए भी इस कोष का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई जुलाई 2024 में घटकर तीन महीने के निचले स्तर 2.04 प्रतिशत पर आ गई।

यह जून में 3.36 प्रतिशत थी। खास बात यह भी है कि 12 अगस्त को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 में खुदरा महंगाई दर घटकर 3.54 फीसदी रह गई है, जबकि जून 2024 में खुदरा महंगाई दर 5.08 प्रतिशत थी। सुकूनदेह स्थिति यह है कि खुदरा महंगाई दर पिछले 5 वर्षों के सबसे कम और रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत के लक्ष्य से भी नीचे आ जाने से अर्थव्यवस्था को मजूबती मिलते हुए दिखाई देगी। इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि बेहतर मानसून से खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों विशेषतया आलू, प्याज और टमाटर आदि की कीमतों में बड़ी कमी आने से खुदरा महंगाई दर में कमी आई है। पिछले दिनों 8 अगस्त को आरबीआई ने देश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत रेपो रेट को पहले की तरह 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। यह लगातार 9वीं बार है जब मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में रेपो रेट को यथावत रखने का फैसला किया गया है। आखिरी बार रेपो रेट में फरवरी 2023 में बदलाव किया गया था। इस मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत तेज विकास दर की बजाय महंगाई नियंत्रण को प्राथमिकता दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि निरंतर आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अभी भी महंगाई पर स्पष्ट तरीके से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। रिजर्व बैंक और सरकार के समन्वित प्रयासों से महंगाई नियंत्रण के लगातार रणनीतिक कदम जरूरी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक वर्ष 2024-25 के बजट के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग को दाम स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के लिए जो धनराशि सुनिश्चित की गई है, उससे खाद्य भंडारण से जुड़ी एजेंसियों को धन मुहैया कराया जाएगा, ताकि वे उपयुक्त भंडारण बनाने के लिए किसानों के खेत या मंडी से सीधे खरीददारी कर सकें।

इसके अलावा नए बजट के तहत इस वर्ष खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग के लिए ऋणों की राशि दोगुनी करके 50000 करोड़ रुपए सुनिश्चित की गई है। निःसंदेह नए बजट के तहत कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे अधिक खाद्यान्न उत्पाद और महंगाई नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलेगा। प्राकृतिक खेती पर भारी प्रोत्साहन सुनिश्चित किए गए हैं और आगामी दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देशभर में 10 हजार बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे, जहां से प्राकृतिक खेती की गतिविधियां संचालित होंगी। मौसम की मार के कारण खराब होने वाली फसलों के लिए समर्थन राशि बढ़ाई जाने से कृषि को नया प्रोत्साहन मिलेगा। नए बजट में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने, दलहन-तिलहन की पैदावार बढ़ाकर और किसानों की आय बढ़ाने, बीज की समस्या के निराकरण और मुख्य फसलों की उत्पादकता प्रभावित होने जैसे मामलों की चुनौतियों को कम करने के साथ-साथ कृषि शोध के विकास के लिए ज्यादा प्रावधान किए हैं। गौरतलब है कि 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) परिसर के खेतों में जाकर 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्में जारी करते हुए कहा कि इनसे देश में कम जमीन में अधिक पैदावार लेने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इससे महंगाई से भी बचाव होगा। इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि सरकार को इस वर्ष जो बेहतर मानसून विरासत में मिला है, उससे भी महंगाई में और कमी आएगी। पूरे देश के कोने-कोने में बेहतर मानसून के लाभ दिखाई देने लगे है। कृषि मंत्रालय ने 12 अगस्त को खरीफ फसलों का रकबा बढने संबंधी रिपोर्ट में कहा है कि चालू खरीफ सीजन में अब तक खरीफ फसलों की बोआई 980 लाख हेक्टेयर के स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले साल की समान अवधि में 966 लाख हेक्टेयर ही थी। इस साल अच्छे मानसून से दाल, तिलहन और अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और इनकी सप्लाई बढने से इनकी कीमतें कम होंगी। बेहतर मानसून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिससे ग्रामीण इलाके में खपत बढ़ेगी। निश्चित रूप से रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, सरकार के वित्तीय नियंत्रण और बेहतर मानसून से जिस तरह महंगाई में कमी आई है, अब इसे नियंत्रित रखने के साथ-साथ ग्रामीण भारत की आर्थिक ताकत में इजाफा करने के लिए कुछ अहम बातों पर ध्यान दिया जाना जरूरी होगा।

इस समय ग्रामीण भारत में जल्द खराब होने वाले ऐसे कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने पर प्राथमिकता से काम करना होगा, जिनकी खाद्य महंगाई के उतार-चढ़ाव में ज्यादा भूमिका होती है। ऐसे में सरकार को खाद्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कृषि उपज की बर्बादी को रोकने के बहुआयामी प्रयासों की कारगर रणनीति पर आगे बढना होगा। हम उम्मीद करें कि अगस्त 2024 में जिस तरह खुदरा उपभोक्ता महंगाई रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित चार फीसदी के लक्ष्य से भी कम है, उसी तरह सरकार भविष्य में भी खुदरा महंगाई दर को पूर्णतया नियंत्रित रखने के लिए बहुआयामी प्रयास करेगी। हम उम्मीद करें कि सरकार नए दाम स्थिरीकरण कोष तथा खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग के लिए किए गए प्रभावी बजट आवंटनों के कारगर उपयोग पर शुरुआत से ध्यान देगी। साथ ही सरकार कृषि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, खाद्य पदार्थों की बरबादी को कम करने, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाए जाने, जलवायु अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणाली अपनाए जाने, अधिक ग्रामीण कच्ची सडक़ों को मंडियों से जोडने जैसी नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से खाद्य वस्तुओं की महंगाई को नियंत्रित रखने के कारगर प्रयासों की डगर पर लगातार आगे बढ़ेगी।

ज्ञान

आर्थिक डेस्टिनेशन-8

शांता कुमार के बाद हिमाचल के प्राकृतिक संसाधनों में आर्थिकी ढूंढने की दृष्टि का सूत्रपात, वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी किया है। वाटर पर सैस के आर्थिक आधार को अगर अनुमति मिल जाए तो यह प्रदेश करीब चार हजार करोड़ आय के स्थायी स्रोत का हकदार हो जाएगा। अभी हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने प्राकृतिक संसाधनों पर राज्यों के अधिकारों को वैधता दी है और अगर इसी भावना का परिचायक पानी बनता है, तो राज्य को विद्युत उत्पादन में मुफ्त बिजली की रॉयल्टी के बाद यह दूसरी सौगात होगी। इसी के साथ बीबीएम से पंजाब पुनर्गठन की लेनदारी तथा सरकारी उपक्रमों से बिजली की रॉयलटी भी जुड़ जाए, तो आर्थिक रिक्तता के कई खाने भर सकते हैं। शानन विद्युत परियोजना की लीज समाप्ति के बाद इसका हस्तांतरण राज्य के वित्तीय खाते की ऐसी उपज है, जिसका कानूनी हल होना चाहिए। शांता कुमार जब विद्युत में मुफ्त की रॉयल्टी लाए थे, तो केंद्र में नरसिंहा राव सरकार थी। ऐसे में हिमाचल के दोनों पक्षों को मिल कर केंद्र से अपने आर्थिक आत्मसम्मान के लिए एकजुटता से प्रयास करने होंगे। इतना ही नहीं पर्यावरणीय या वन आर्थिकी की भरपाई तथा राष्ट्रीय योजनाओं-परियोजनाओं में पर्वतीय राज्यों की आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। देश में पर्वतीय राज्यों के करीब चार दर्जन सांसद अगर एक जुट होकर मांग करें, तो एक स्वतंत्र 'पर्वतीय विकास मंत्रालय' का गठन करवाया जा सकता है। मसले अरुणाचल से जम्मू-कश्मीर तक अगर पर्वतीय मानदंडों, विकास की जरूरतों और आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप समझे जाएं, तो हिमाचल जैसे राज्य के कई बंद द्वार खुल जाएंगे। बहरहाल सुक्खू सरकार ने राज्य की आय बढ़ाने के लगभग एक दर्जन रास्तों पर चलने का इरादा जाहिर किया है। लगभग पच्चीस सौ करोड़ आय बढ़ाने के उपायों में आबकारी एवं कराधान को नए संकल्प और नई नीति से जोड़ते हुए शराब के ठेकों की बिक्री से अतिरिक्त छह सौ करोड़ जुटाने का इरादा सामने आया है।

शून्य संख्या के 99 स्कूलों को बंद करना या 460 को मर्ज करना समय की जरूरत है, लेकिन इस पैगाम को अनावश्यक दफ्तरों की पैमाइश तक ले जाना होगा। घाटे के एचआरटीसी को अगर 1966 करोड़ के बोझ से उबारना है, तो कई बस डिपो, बस रूट तथा अनावश्यक अधिकारियों का टोला कम करना पड़ेगा। प्रसन्नता का विषय यह कि प्रदेश में डेढ़ सौ से तीन सौ यूनिट तक बढ़ी मुफ्त बिजली की गारंटी को अब यह होश आ गया कि यह प्रति व्यक्ति आय में देश की औसत से आगे चल रहे हिमाचलियों को न देकर नौ सौ करोड़ की बचत होगी। हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद, पावर कारपोरेशन तथा ट्रांसमिशन कारपोरेशन के कुल घाटे को देखा जाए तो 2885.79 करोड़ के आंकड़े के नीचे कई अरमान दबे हैं। हिमाचल के कमाऊ दस विभागों को आगे बढने का मौका मिलना चाहिए। मसलन हिमुडा को नागरिक मांग के अनुरूप शहर बसाने चाहिएं, तो औद्योगिक विकास निगम को आई टी पार्क। सिविल सप्लाई कारपोरेशन व खादी ग्रामीण उद्योग को अपने कार्य का दायरा बढ़ाना होगा। हिमाचल सरकार की सबसे अहम आर्थिक डेस्टिनेशन बन कर उभर रही कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना प्रदेश की अगली सदी बदल सकती है। जिस तरीके व उदारता से हिमाचल सरकार एयरपोर्ट विस्थापितों का पुनर्वास कर रही है, यह अपने आप में एक उदाहरण बनने जा रहा है। एयरपोर्ट विस्तार के साथ अगर एक आर्थिक व पर्यटन गलियारा भी विकसित हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसी तरह काला अंब, बीबीएन, बीबीटी से संसारपुर टैरेस तक के सीमांत क्षेत्र को औद्योगिक गलियारे की परिभाषा में विकसित किया जाए, तो निश्चित रूप से कल हिमाचल एक आत्मनिर्भर एवं संपन्न राज्य बन सकता है।

वैदिक ज्ञान व संस्कृत भाषा की कालातीत यात्रा

डा. अमरीक सिंह ठाकुर

संस्कृत सप्ताह का लक्ष्य शैक्षणिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इसे संरक्षित करने का है'

संस्कृत, जिसे 'देवताओं की भाषा' के रूप में जाना जाता है, संसार की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसने भारतीय सभ्यता को आकार दिया है और आधुनिक समय में भी इसकी प्रासंगिकता जारी है। यह केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता का गहरा भंडार है। संस्कृत वह माध्यम है जिसके माध्यम से प्राचीन वैदिक ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों और विभिन्न अन्य शास्त्रों की रचना की गई, जिससे यह सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की आधारशिला बन गई। रक्षा बंधन से तीन दिन पहले शुरू होने वाला और तीन दिन बाद समाप्त होने वाला संस्कृत सप्ताह श्रावण की पूर्णिमा के दिन के साथ मेल खाता है, जो भारतीय पारंपरिक कैलेंडर में एक शुभ अवधि को चिह्नित करता है। यह उत्सव न केवल संस्कृत भाषा संवर्धन के लिए एक शुभ अवधि है, बल्कि प्राचीन वैदिक ज्ञान के समृद्ध भंडार में तल्लीन करने का एक अवसर भी है, जो संस्कृत सप्ताह प्रदान करता है। सप्ताह अकादमिक गतिविधियों, साहित्यिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बहुत कुछ से भरा है, जिसका उद्देश्य इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। संस्कृत को अक्सर मानव सभ्यता की सबसे पुरानी भाषा के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं।

यह वह भाषा है जिसमें दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात ग्रंथ ऋग्वेद की रचना की गई थी। संस्कृत सिर्फ एक भाषा से अधिक है, यह एक विशाल बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपरा का अवतार है, जिसने भारत और उसके बाहर जीवन के अनगिनत पहलुओं को प्रभावित किया है। संस्कृत भाषा को हिंदू धर्म में देवताओं की भाषा के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिसका उपयोग अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और समारोहों में किया जाता है, जो व्यक्तियों को परमात्मा से जोड़ते हैं। संस्कृत की संरचना इतनी सटीक है और इसकी ध्वन्यात्मकता इतनी समृद्ध है कि इसे आध्यात्मिक प्रवचन के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। वैदिक परंपरा, जो सनातन धर्म की नींव बनाती है, अपने पवित्र ज्ञान के प्रसारण के लिए संस्कृत पर बहुत अधिक निर्भर करती है। वैदिक परंपरा में, 16 संस्कार (पारित होने के संस्कार) हैं, जो महत्वपूर्ण अनुष्ठान हैं जो किसी व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक मार्गदर्शन करते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण उपनयन संस्कार 10वां संस्कार है, जो एक बच्चे की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक है। यह अनुष्ठान आमतौर पर श्रावण पूर्णिमा पर किया जाता है। उसी दिन इस समारोह के दौरान, संस्कृत में गायत्री मंत्र के पाठ के साथ बच्चे को वैदिक शिक्षा में दीक्षित किया जाता है। यह दीक्षा ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा की दुनिया में बच्चे के प्रवेश का प्रतीक है, जो व्यक्तियों के शैक्षिक और आध्यात्मिक जीवन में संस्कृत के महत्व को रेखांकित करती है। संस्कृत की प्रासंगिकता प्राचीन ग्रंथों और अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है। यह आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन के साथ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल करने पर जोर देती है, जिनमें से संस्कृत एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 संस्कृत को आधुनिक शिक्षा, समकालीन विद्वानों और प्राचीन भारतीय ज्ञान के विशाल भंडार के बीच एक सेतु के रूप में पहचानती है।

भारत सरकार 1969 से संस्कृत दिवस मना रही है, और 2000 में, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान, संस्कृत सप्ताह की आधिकारिक घोषणा की गई थी। इस उत्सव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अधिक महत्व मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने शिक्षा में संस्कृत की भूमिका को और मजबूत किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें प्राचीन ग्रंथों, शास्त्रों और दर्शनों के अध्ययन पर जोर दिया गया है, जो मुख्य रूप से संस्कृत में है। संस्कृत को आधुनिक तकनीक में अपनी क्षमता के लिए भी तेजी से पहचाना जाता है, विशेष रूप से कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। भाषा का संरचित वाक्यविन्यास और व्याकरण इसे प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए एक उत्कृष्ट भाषा बनाता है और इसका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों में खोजा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर के देश, जहां नासा जैसे संस्थानों ने रुचि दिखाई है, विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में संस्कृत की क्षमता का पता लगाने लगे हैं। संस्कृत सप्ताह भाषा को उसके सभी पहलुओं (साहित्यिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक) में मनाने का समय होता है। सप्ताह भर चलने वाले उत्सव में छात्रों, विद्वानों और आम जनता को संस्कृत के साथ जोडने के लिए डिजाइन की गई कई गतिविधियां शामिल हैं। भाषा के विभिन्न पहलुओं और समकालीन समय में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करने के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार, सम्मेलन और संगोष्ठी आयोजित की जाती हैं। ये कार्यक्रम विद्वानों को अपने शोध प्रस्तुत करने, विचारों का आदान-प्रदान करने और संस्कृत के अध्ययन और उपयोग को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। साहित्यिक गतिविधियां, जैसे कविता पाठ, कहानी कहने के सत्र और संस्कृत में वाद-विवाद भी समारोहों का एक हिस्सा हैं। इन घटनाओं का उद्देश्य भाषा की सुंदरता और बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करना है।

यह दर्शाता है कि संस्कृत केवल अतीत की भाषा नहीं है, बल्कि आज भी बहुत जीवित है। पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं जिन्हें संस्कृत ने संरक्षित करने में मदद की है। बहरहाल, संस्कृत सप्ताह का उत्सव शैक्षणिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भाषा की कालातीत प्रासंगिकता और समाज के आध्यात्मिक, बौद्धिक और तकनीकी विकास में योगदान करने की इसकी क्षमता की याद दिलाता है। जैसा कि हम संस्कृत सप्ताह मनाते हैं, आइए हम भाषा की समृद्ध विरासत को अपनाएं और एक उज्ज्वल, अधिक जुड़े भविष्य को आकार देने में इसकी क्षमता का पता अनिवार्य रूप से लगाएं।

भारत विरोधी कश्मीर की बात

जम्मू-कश्मीर चुनाव के मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने घोषणा-पत्र जारी किए हैं, जो बुनियादी तौर पर भारत-विरोधी लगते हैं। 1950 के दशक में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और शेख अब्दुल्ला की अपनी-अपनी लड़ाइयां और सियासत थी। शेख अब्दुल्ला कश्मीर को 'इस्लामी सूबा' बनाने पर आमादा थे। उन्हें प्रधानमंत्री का दर्जा हासिल था। श्यामा प्रसाद ने 'एक विधान, एक निशान, एक प्रधान' की व्यवस्था के लिए संघर्ष किया। उनकी रहस्यमयी मौत आज भी एक सवाल है। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने से पहले जम्मू-कश्मीर का अपना 'झंडा' था, अपना 'संविधान' था। कश्मीर में सर्वोच्च अदालत के फैसले भी लागू नहीं होते थे। भारतीय दंड संहिता की धाराएं भी निष्प्रभावी थीं। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल होता था। रक्षा, विदेश, वित्त आदि मंत्रालय भारत सरकार के अधीन थे, लेकिन उनके अलावा कश्मीर के कानून और व्यवस्थाएं भिन्न थीं। आर्थिक संसाधनों और बजट के लिए जम्मू-कश्मीर भारत सरकार के सहारे ही था। सवाल होते रहते थे कि एक ही राष्ट्र में कश्मीर को यह 'विशेष दर्जा' क्यों हासिल है? दो-दो व्यवस्थाएं कैसे काम कर सकती हैं? मोदी सरकार ने ऐतिहासिक पहल की और 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त करने का बिल संसद से पारित करा दिया। अब 2024 में विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई है, तो पुराने मुद्दों को नए संदर्भों में उठाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अनुच्छेद 370, 35-ए की बहाली का आश्वासन दिया है। जम्मू-कश्मीर के 'अलग झंडे' की बात कही गई है। ऐसा है, तो आने वाली विधानसभा में 'अलग संविधान' का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। इसके लिए दलीलें दी जाती रही हैं कि विलय के समझौता-पत्र में उल्लेख था कि कश्मीर का अपना 'अलग झंडा' और 'अलग संविधान' होगा। ये दलीलें कुतर्क हैं, क्योंकि विलय-पत्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सियासतदानों को जरा पढ़ लेना चाहिए। बहरहाल पत्थरबाजों की दोबारा सरकारी नौकरी में बहाली होगी और जेल से सियासी कैदियों की रिहाई की जाएगी। ऐसे कैदियों को माफ भी किया जा सकता है। पाकिस्तान से सटी 'नियंत्रण रेखा' पर कारोबार की नई शुरुआत के साथ-साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत और जनसंपर्क भी शुरू किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सोच के स्तर पर पाकपरस्त रही हैं, लेकिन सवाल है कि क्या एक विधानसभा ऐसे मुद्दों को पारित कर सकती है? विदेश और रक्षा नीतियां केंद्र सरकार तय करेगी अथवा संघशासित क्षेत्र की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है?

भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त किया था और सर्वोच्च अदालत ने भी उसे 'उचित, संवैधानिक निर्णय' माना था। तो विधानसभा चुनाव में पार्टियां इनकी बहाली और 'विशेष दर्जे' की वापसी का वायदा कैसे कर सकती हैं? यह सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पूछा गया था। उनका जवाब था कि आने वाली सर्वोच्च अदालत में कश्मीर की बुनियादी सोच वाले न्यायाधीश भी आ सकते हैं! केंद्र में मौजूदा सरकार की विदाई हो सकती है तथा विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की सरकार बन सकती है! हमने जम्मू-कश्मीर के अवाम को आश्वस्त किया है कि तब तक हम इंतजार करेंगे, लेकिन लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। एक घोषणा-पत्र में कहा गया है कि 'शंकराचार्य के पर्वत' का इस्लामी नाम 'तख्त-ए-सुलिमान' रखा जाएगा। क्या कश्मीर को एक बार फिर 'इस्लामिक' बनाने के मंसूबे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो शेख अब्दुल्ला की ही विरासत है, लिहाजा उनकी सियासत भी वही होगी। पीडीपी ने यहां तक घोषणा की है कि 'जमात-ए-इस्लामी' पर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। यानी कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, हड़ताल और बंद की पुरानी स्थितियों की वापसी के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं? घोषणा-पत्र में आरक्षण खत्म करने का आश्वासन दिया गया है। क्या गुर्जर, बक्करवाल, दलित, पहाड़ी जातियों के आरक्षण खत्म किए जाएंगे? यह निर्णय कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति पर आघात की तरह साबित हो सकता है। ऐसे कई आश्वासन घोषणा-पत्रों में दिए गए हैं। बेशक ये देश-विरोधी घोषणाएं हैं।

क्या किराना स्टोर्स का खत्म हो जाएगा वजूद, क्विक कॉमर्स से क्यों डर रहे दुकानदार?

परिवहन विशेष न्यूज

किराना स्टोर्स! राशन-पानी से लेकर दूसरे रोजमर्रा समान लेने का ठिकाना। यहां आप थोड़ा मोल-भाव कर लेते हैं। पुराने ग्राहक हैं तो समान उधार भी मिल जाता है। कुल मिलाकर हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं ये पड़ोस की दुकानें यानी किराना स्टोर्स। ये लंबे समय से अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। लेकिन अब इनका वजूद खतरे में हैं।

नई दिल्ली। 'किराना स्टोर के मुकाबले क्विक कॉमर्स से सामान मंगाना सस्ता पड़ता है। मैं टूथपेस्ट और कुछ दूसरे सामान के लिए किराना स्टोर पर गया। वहां पर दुकानदार ने मुझे बताया 265 रुपये। उन्हीं चीजों को मैंने अपने क्विक प्लेटफॉर्म के कार्ट में भी एड कर रखा था और वे मुझे मिल रहे थे 190 रुपये में। अगर मुझे सस्ता सामान अपने घर पर मिल जा रहा है, तो वही सामान मैं दुकान पर जाकर महंगे में क्यों लूंगा।'

यह कहना है नोएडा के रहने वाले शुभम का, जो किराना स्टोर को छोड़कर क्विक कॉमर्स से राशन और रोजमर्रा के दूसरे सामान मंगा रहे हैं। सुभाष की तरह लाखों शहरी उपभोक्ता हैं, जो अब किराना स्टोर्स को छोड़कर ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का रुख कर रहे हैं। इसकी वजह से किराना स्टोर्स के वजूद पर गंभीर संकट भी खड़ा हो गया है।

किराना स्टोर्स क्यों खतरे में हैं?

किराना स्टोर्स को सबसे अधिक खतरा है क्विक कामर्स से, जो सिर्फ 10 मिनट राशन का सामान घर पहुंचाने का दावा करते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी केंद्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों के तेजी से विस्तार पर चिंता जता चुके हैं। उनकी नजर में यह उपलब्धि नहीं, बल्कि 'चिंता का विषय' है।

केंद्रीय मंत्री ने पिछले दिनों छोटे मोबाइल स्टोरों की घटती संख्या का जिक्र किया है। उन्होंने कहा, 'अब आप बाजारों में कितने मोबाइल स्टोर देखते हैं और 10 साल पहले कितने थे?' उन्होंने ईकॉमर्स की प्रीडेटरी प्राइसिंग यानी काफी छूट के साथ सामान बेचने को भी खतरनाक चलन बताया।

देश में करीब 1.2 करोड़ किराना स्टोर हैं। इनका सालाना कारोबार 800 अरब डॉलर से अधिक का है। ये किराने का सामान, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और दूसरी चीजें बेचते हैं। किराना स्टोर से जनता की रोजमर्रा की जरूरतें तो पूरी ही होती हैं, ये रोजगार के भी बड़े साधन हैं। यही वजह है कि सरकार भी किराना स्टोर्स के वजूद को लेकर चिंतित है।

फ्लॉप से हिट कैसे हुए क्विक कॉमर्स?

ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पारंपरिक किराना स्टोर को तेजी से पीछे छोड़ रहे हैं। हालांकि, जब कोरोना महामारी के वक्त क्विक कॉमर्स की शुरुआत हुई, तो इन्हें लेकर लोगों का नजरिया काफी रुढ़िवादी था। उनका मानना था कि भारतीय उपभोक्ता ऐसी सेवाओं के बदले पैसा नहीं देने वाले, चाहे जो हो जाए। कुछ लोगों तो यहां तक कहना था कि उपभोक्ता कुछ घंटों तो क्या, मुफ्त डिलिवरी के लिए एक दिन का भी इंतजार कर लेंगे।

क्विक कॉमर्स मॉडल ज्यादातर देशों में नाकाम भी हो चुका था। लेकिन, भारत में इसे गजब की सफलता मिली। ये झटपट सामान पहुंचा देते हैं, जो हाउस वाइफ और बैचलर को काफी पसंद आ रहा है। शहरों में वैसे भी समय को पैसे माना जाता है और इसे बचाने के लिए लोग थोड़ा-बहुत भुगतान करने को खुशी-खुशी तैयार हैं।

नेस्ले, पारले, आईटीसी, मैरिको और इमामी जैसी FMCG कंपनियों की सालाना ईकॉमर्स बिक्री में क्विक कॉमर्स का योगदान 30-50 फीसदी तक पहुंच गया है। इसमें आगे भी तेजी आने का अनुमान है।

कैसे बचेगा किराना स्टोर्स का वजूद?

अगर किराना दुकानों को जीवित रहना है, तो उन्हें तेजी से डिजिटल होना होगा। कुछ किराना स्टोर्स वॉट्सऐप जैसे माध्यमों से होम डिलिवरी की सुविधा देते हैं। लेकिन, डिलिवरी के मामले में उनकी क्षमता सीमित है। जैसे कि अगर एकसाथ तीन-चार ग्राहकों ने ऑर्डर कर दिया, उनके लिए समय पर सामान पहुंचाना मुश्किल हो जाता है।

किराना स्टोर्स के लिए अच्छी बात यह भी है कि उनके पास खुला स्टॉक बेचने की सहूलियत रहती है, जो क्विक कॉमर्स के लिए बड़ी चुनौती है। जैसे कि किराना स्टोर दो-तीन किलो खुला आटा-चावल भी बेच सकते हैं, लेकिन क्विक कॉमर्स नहीं।

अधिकांश किराना स्टोर्स अपने ग्राहकों को 'खाता सिस्टम' की सुविधा देते हैं। इसमें सामानों का हिसाब का एक निश्चित समय पर होता है। यह एक हफ्ता, एक महीना या एक साल भी हो सकता है। लेकिन, क्विक कॉमर्स के लिए ऐसी सहूलियत दे पाना मुश्किल है। खासकर, छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में।

रिलायंस का मॉडल भी उम्मीद की किरण

क्विक कॉमर्स और किराना स्टोर्स के बीच गठजोड़ भी किराना स्टोर्स को बचा सकता है। अभी अधिकतर क्विक कॉमर्स के पास अपना डॉर्क स्टोर है, जहां से वे उपभोक्ताओं को सामान की डिलिवरी करते हैं। लेकिन, अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब इस दिशा में पहल भी करने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्री की खुदरा शाखा रिलायंस रिटेल भी क्विक कॉमर्स सेगमेंट में दोबारा एंट्री करने वाली है।

हालांकि, रिलायंस रिटेल 10 मिनट डिलिवरी मॉडल के साथ ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट और जेप्टो से सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। इसमें प्रोडक्ट को लाखों किराना स्टोर से खरीदा जाएगा, जो अपना माल रिलायंस रिटेल मंगाएंगे और फिर उसकी उपभोक्ताओं को डिलिवरी की जाएगी। किराना स्टोर JioMart पार्टनर पहल का हिस्सा हैं, जिसके तहत वे रिलायंस रिटेल की थोक शाखा से उत्पाद खरीदते हैं।

अप्रैल-जून में औसत घर की कीमत सालाना 12 प्रतिशत बढ़ी; NCR में 30 प्रतिशत की वृद्धि: रिपोर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

नई रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि आठ प्रमुख शहरों में औसत आवास की कीमतों में सालाना 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में यह बढ़ोतरी 8652 रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़कर 11279 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गई। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। क्रेडाई, कोलियर्स और लियासेस फोरास की एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-जून तिमाही के दौरान आठ प्रमुख शहरों में औसत आवास की कीमतों में सालाना 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

रियलटर्स बॉडी क्रेडाई, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोलियर्स और डेटा एनालिटिक फर्म लियासेस फोरास ने 'हाउसिंग प्राइस-ट्रैकर रिपोर्ट Q2 2024' जारी की है। वार्षिक आधार पर, जून तिमाही के अंत में औसत आवास की कीमतों में आठ प्रमुख शहरों में 12 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

दिल्ली-एनसीआर सबसे आगे

दिलचस्प बात यह है कि समीक्षाधीन 8 में से 7 शहरों में वार्षिक मूल्य वृद्धि देखी गई, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में सबसे अधिक 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा कि पिछले कुछ तिमाहियों में रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी देखी गई है, जिसकी पुष्टि शीर्ष 8 शहरों में लेनदेन की मात्रा के साथ-साथ आवास के प्रति प्रचलित सकारात्मक भावनाओं से होती है।

आवास की कीमतों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है - यह न केवल अंतर्निहित मांग को दर्शाता है, बल्कि एक पसंदीदा परिसंपत्ति वर्ग के रूप में रियल एस्टेट की ओर निश्चित बदलाव को भी दर्शाता है।

अन्य शहरों में आवास की कीमतें

आंकड़ों के अनुसार, अहमदाबाद में आवास की कीमतें अप्रैल-जून 2024 में 13 प्रतिशत बढ़कर 7,335 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गईं, जो एक साल पहले की अवधि में 6,507 रुपये प्रति वर्ग फीट थीं।

बेंगलुरु में 8,688 रुपये प्रति वर्ग फीट से 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,161 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गई।

चेन्नई में कीमतें 7,690 रुपये प्रति वर्ग फीट पर स्थिर रहीं। दिल्ली-एनसीआर में कीमतों में अधिकतम 30 प्रतिशत की वृद्धि

देखी गई, जो 8,652 रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़कर 11,279 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गई।

हैदराबाद में आवास की कीमतें 10,530 रुपये प्रति वर्ग फीट से 7 प्रतिशत बढ़कर 11,290 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गईं। कोलकाता में, दरें 7,315 रुपये प्रति वर्ग फीट से 6 प्रतिशत बढ़कर 7,745 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गईं।

मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में आवास की कीमतें 19,111 रुपये प्रति वर्ग फीट से 6 प्रतिशत बढ़कर 20,275 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गईं।

पुणे में, आवासीय संपत्तियों की कीमतें अप्रैल-जून 2024 में 13 प्रतिशत बढ़कर 9,656 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गईं, जो एक साल पहले की अवधि में 8,540 रुपये प्रति वर्ग फीट थीं।

लियासेस फोरास के प्रबंध निदेशक पंकज कपूर ने कहा, रकीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत के शहरों में बिक्री में वृद्धि जारी है। कोलियर्स इंडिया के सीईओ बादल याग्निक ने कहा कि पिछली कुछ तिमाहियों में आवास की मांग लगातार अच्छी बनी हुई है।

साथ ही, स्थिर ब्याज दरों और हाल ही में सकारात्मक बजटीय घोषणाओं ने देश के आवास बाजार को बढ़ावा दिया है। उन्हें 2024 में आवास बाजार के लिए मजबूत समापन की उम्मीद है।

LPG की कीमतों के साथ रविवार से होंगे 6 बड़े बदलाव, आपकी जेब से सीधा है इसका कनेक्शन

नई दिल्ली। आने वाले रविवार से सिंतबर (September 2024) महीने की शुरुआत हो जाएगी। इसका मतलब है कि यह अगस्त का आखिरी हफ्ता चल रहा है। हर महीने कई बड़े बदलाव होते हैं। इन बदलावों का असर आम जनता की बजट (Budget) पर पड़ता है। 1 सितंबर 2024 से 6 बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों में से एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत (LPG Cylinder Price) भी है। आइए, जानते हैं कि आने वाले रविवार से कौन-से बड़े बदलाव होंगे।

LPG सिलेंडर के दाम

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों (LPG Cylinder Price) को अपडेट किया जाता है। तेल कंपनी कमर्शियल गैस सिलेंडर (Commercial Cylinder) और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को अपडेट करती है। 1 सितंबर को इन दोनों सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखा जा सकता है। अगस्त में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर के दाम को स्थिर रखा और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8.50 रुपये की बढ़ोतरी की थी।

ATF और CNG-PNG प्राइस

एलपीजी सिलेंडर के साथ तेल कंपनियां हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) और सीएनजी-पीएनजी (CNG-PNG) के दाम को भी अपडेट करती हैं। 1 सिंतबर 2024 को इनकी कीमतों में भी बदलाव हो सकता है।

ट्राई के नए नियम (TRAI New Rule)

फेक कॉल और मैसेज पर रोक लगाने के लिए TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है। इसके लिए ट्राई ने सख्त गाइडलाइन्स भी जारी किया है। ट्राई ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल आदि टेलीकॉम कंपनी को निर्देश दिया है कि वह 30 सितंबर तक 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल और कमर्शियल मैसेजिंग को ब्लॉकचेन बेस डीएलटी यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करें। ट्राई के नए गाइडलाइन्स के बाद उम्मीद की जा रही है कि 1 सितंबर से फर्जी कॉल और मैसेज पर रोक लग जाएगी।

क्रेडिट कार्ड के नियम (Credit Card Rule)

देश के सबसे बड़ा बैंक HDFC Bank 1 सितंबर से क्रेडिट कार्ड के नियमों (Credit Card Rule) में बदलाव करने जा रहा है। बैंक यूटिलिटी ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड प्वाइंट की लिमिट निर्धारित करेगा। इसके अलावा बैंक अब थर्ड पॉर्टी ऐप से एजुकेशनल पेमेंट करने पर कोई रिवॉर्ड प्वाइंट भी नहीं देगा।

सितंबर 2024 से IDFC First Bank के क्रेडिट कार्ड पर देय मिनिमम अमाउंट कम होने वाला है। बैंक ने पेमेंट की तारीख भी 15 दिन कर दिया है जो कि पहले 18 दिन थी। इसके अलावा 1 सिंतबर से यूपीआई पेमेंट (UPI Payment) के लिए RuPay क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ग्राहकों को बाकी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के क्रेडिट कार्ड जितना ही रिवॉर्ड प्वाइंट मिलेगा।

वैध बैंक खाते के बिना दाखिल नहीं हो सकेगा GST रिटर्न

जीएसटी नेटवर्क ने बीते शुक्रवार यानी 26 अगस्त को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि एक सितंबर 2024 से नियम 10ए लागू हो रहा है। ऐसे में करदाता बिना वैध बैंक खाता अगस्त 2024 के लिए न तो जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे और न ही इनवायस तैयार करने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। आइये इसके बारे में जनते हैं।

नई दिल्ली। जिन जीएसटी करदाताओं ने जीएसटी प्राधिकरण को अपने बैंक खाते के विवरण नहीं दिया है, वे एक सितंबर से जीएसटीआर-1 के जरिये अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। जीएसटी नेटवर्क ने एक एडवाइजरी में यह जानकारी दी है।

जीएसटी नियम 10A के अनुसार, करदाता को पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के भीतर या पहली बार जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय या इनवॉयस तैयार करने की सुविधा का इस्तेमाल करते समय अपने वैध बैंक खाते का विवरण देने की जरूरत होती है।

23 अगस्त को जारी की एडवाइजरी

जीएसटी नेटवर्क ने 23 अगस्त को जारी एक एडवाइजरी में कहा है कि एक सितंबर 2024 से नियम 10ए लागू हो रहा है। ऐसे में करदाता बिना वैध बैंक खाता अगस्त 2024 के लिए न तो जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे और न ही इनवायस तैयार करने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे।

जीएसटी नेटवर्क ने कहा है कि जिन करदाताओं ने अभी तक जीएसटी पोर्टल पर अपने बैंक खाते का विवरण नहीं दिया है, वे जल्द से जल्द अपने पंजीकरण विवरण में बैंक खाते की जानकारी दे दें।

जीएसटी काउंसिल ने पिछले वर्ष जुलाई में आयोजित बैठक में पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने और फर्जी पंजीकरणों की समस्या से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधनों को मंजूरी दी थी। संशोधन में करदाता के नाम और पैन वाले बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया गया था।

रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी ला रही 835 करोड़ का IPO, 30 अगस्त को होगा ओपन

परिवहन विशेष न्यूज

रेखा झुनझुनवाला के वैल्यू फैशन रिटेलर बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड ने अपने 835 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 370-389 रुपये प्रति शेयर का मूल्य बैंड तय किया है। जानकारी मिली है कि आरंभिक शेयर सेल 30 अगस्त को सार्वजनिक सदस्यता के लिए खुलेगी और 3 सितंबर को समाप्त होगी। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। वैल्यू फैशन रिटेलर बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसने अपने 835 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 370-389 रुपये प्रति शेयर का मूल्य बैंड तय किया है।

कंपनी ने घोषणा की कि आरंभिक शेयर बिक्री 30 अगस्त को सार्वजनिक सदस्यता के लिए खुलेगी और 3 सितंबर को समाप्त होगी। प्रस्तावित आईपीओ 148 करोड़ रुपये मूल्य के इक्विटी शेयरों के नए निर्गम और प्रमोटर समूह संस्थाओं और अन्य विक्रय शेयरधारकों द्वारा मूल्य बैंड के ऊपरी छोर पर 687 करोड़ रुपये मूल्य के 1.76 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है।

कर्ज के भुगतान में 146 करोड़ रुपये का उपयोग

इसके साथ, कुल इश्यू का आकार ऊपरी और मूल्य बैंड 389 रुपये पर 835 करोड़ रुपये होगा। ओएफएस के तहत, रेखा झुनझुनवाला, इंटेंसिव सॉफ्टशेयर प्राइवेट लिमिटेड और इंटेंसिव फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेंगे।

ताजा इश्यू से प्राप्त 146 करोड़ रुपये का उपयोग कर्ज के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

इस महीने की शुरुआत में, कोलकाता स्थित कंपनी ने प्री-आईपीओ प्लेसमेंट राउंड में वोल्राडो वेंचर्स पार्टनर्स फंड II से 37 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसके अनुसार, नए इश्यू का आकार घटा दिया गया। बाज़ार स्टाइल रिटेल पश्चिम बंगाल और ओडिशा में वैल्यू रिटेल मार्केट में अग्रणी खिलाड़ियों में से एक है।

मुख्य बाजारों में शामिल हैं ये शहर

इसके अतिरिक्त, इसके अन्य मुख्य और

फोकस बाजारों में असम, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।

निवेशक एक लॉट में न्यूनतम 38 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, साथ ही 38 के गुणकों में अतिरिक्त शेयर भी खरीद सकते हैं।

वित्त वर्ष 2024 में बाज़ार स्टाइल रिटेल का परिचालन से समेकित राजस्व 972.88 करोड़ रुपये रहा और कर के बाद लाभ वित्त वर्ष 2024 में 21.94 करोड़ रुपये रहा।

एक्सिस कैपिटल, इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज और जेएम फाइनेंशियल इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं।

A1 और A2 लेबलिंग के साथ बिकता रहेगा दूध, FSSAI ने वापस लिया अपना फैसला

फूड रेगुलेटर FSSAI का कहना है कि उसने सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि लेबलिंग हटाने से उपभोक्ताओं को दिक्कत हो सकती है। ऐसे में एडवाइजरी को वापस लेने का फैसला किया गया। इसका मतलब है कि डेयरी कंपनियां A1 और A2 लेबलिंग के साथ दूध और दूध से बने उत्पाद बेचना जारी रख सकती हैं।

नई दिल्ली। अब दूध और दूध से बने उत्पाद A1 और A2 लेबल के साथ बिकते रहेंगे। फूड रेगुलेटर FSSAI ने अपनी वह एडवाइजरी वापस ले ली, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स पर A1 और A2 की लेबलिंग हटाने का निर्देश दिया गया था। यह लेबलिंग प्रोटीन के आधार पर गायों के दूध में अंतर बताती है। कुछ रिसर्च में A2 दूध को A1 से बेहतर बताया गया है, लेकिन इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

FSSAI ने एडवाइजरी वापस क्यों ली?

फूड रेगुलेटर FSSAI का कहना है कि उसने सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि लेबलिंग हटाने से उपभोक्ताओं को दिक्कत हो सकती है।

ऐसे में एडवाइजरी को वापस लेने का फैसला किया गया। इसका मतलब है कि डेयरी कंपनियां A1 और A2 लेबलिंग के साथ दूध और दूध से बने उत्पाद बेचना जारी रख सकती हैं।

FSSAI ने पहले क्या कहा था?

FSSAI ने 21 अगस्त की अपनी एडवाइजरी में कहा था कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBO) अपने प्रोडक्ट्स से 'A1 और A2' के दावों को हटा दें। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी इन दावों को उत्पादों और वेबसाइटों से तुरंत हटाने के लिए कहा गया था। फूड रेगुलेटर का कहना था कि 'A1' और 'A2' प्रकार के दूध और दूध उत्पादों के दावे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं हैं।

FSSAI ने जांच के बाद पाया था कि A1 और A2 का अंतर दूध में बीटा-कैसीइन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा हुआ है। फिलहाल FSSAI नियम इस अंतर को मान्यता नहीं देता। 21 अगस्त की एडवाइजरी में फूड रेगुलेटर ने एफबीओ को छह महीने के पुराना स्टॉक खत्म करने और लेबलिंग को आगे जारी नहीं रखने का निर्देश दिया था।

A1 और A2 दूध में क्या अंतर होता है?

A1 और A2 गाय के दूध में पाए जाने वाले बीटा-कैसीन प्रोटीन के बारे में बताता है। A1 प्रोटीन मुख्य रूप से उत्तरी यूरोप की नस्ल वाली गायों के दूध में मिलता है, जैसे कि होलस्टीन। वहीं, A2 प्रोटीन अधिकतर साहीवाल और गिर जैसी भारतीय नस्ल की गायों के दूध में मिलता है। एक्सपर्ट के मुताबिक, दूध में पाया जाने वाला 80 फीसदी प्रोटीन केसीन (Casein) होता है। A1 गाय के दूध में A1 बीटा-केसीन और A2 गाय के दूध में A2 बीटा-केसीन होता है।

पेटीएम के फाउंडर की बढ़ीं मुश्किलें; IPO में गड़बड़ी का आरोप, शेयर हुए धड़ाम

नई दिल्ली। ऑनलाइन पेमेंट सर्विस देने वाली Paytm के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। अब उन पेटीएम का मालिकाना हक रखने वाली One 97 Communications Ltd के आईपीओ में गड़बड़ी का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने विजय शेखर शर्मा और आईपीओ लाने के दौरान One 97 Communications Ltd के बोर्ड में शामिल सदस्यों को नोटिस भेजा है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सेबी को शक है कि विजय शेखर शर्मा ने IPO लाने के दौरान कुछ फैक्ट्स को गलत दिखाया। आसान शब्दों में कहें, तो पूरा मामला यह है कि आईपीओ के दौरान विजय शेखर शर्मा को कंपनी का प्रमोटर माना जाए या नहीं। अगर प्रमोटर माना जाएगा, तो उनके खिलाफ आईपीओ का गलत तरीके से फायदा उठाने का आरोप रहेगा।

सेबी की राय में जब One 97 Communications के आईपीओ से जुड़े दस्तावेज जमा किए गए थे, तो उस समय विजय शेखर के पास कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल था। वह कोई कर्मचारी नहीं थे। यही वजह है कि सेबी ने उन बोर्ड मेंबर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिन्होंने विजय शेखर शर्मा के कर्मचारी वाले फैक्ट को स्वीकार किया।

प्रमोटर-कर्मचारी का बवाल क्यों?

अगर विजय शेखर शर्मा को आईपीओ लाते वक्त प्रमोटर बताया जाता, तो वह ESOP (Employee stock option plan) के लिए अयोग्य हो जाते। सेबी के नियमों के मुताबिक, IPO आने के बाद प्रमोटर्स को ESops नहीं मिलता है। सेबी पहले भी कंपनी के निदेशकों पर एक्शन ले चुकी है। लेकिन, तब मामला वित्तीय हेराफेरी से जुड़ा था।

रिजर्व बैंक (RBI) ने भी इस साल की शुरुआत में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच की थी। उसी से मिले इनपुट के आधार पर अब विजय शेखर शर्मा मार्केट रेगुलेटर की नजरों में आए हैं।

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा: गड्ढों के खतरे

डॉ. अंकुर शरण

सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के संदर्भ में सबसे बड़ा खतरा जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है सड़कों पर बने छोटे-छोटे गड्ढे। ये गड्ढे, जो शुरू में छोटे होते हैं, लेकिन समय के साथ इनकी अनदेखी करने पर यह बड़े गड्ढों में तब्दील हो जाते हैं और पूरी सड़क को क्षतिग्रस्त कर देते हैं।

सड़कों पर बने गड्ढे केवल सड़कों की गुणवत्ता को ही नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। गड्ढों के कारण वाहन चालक असंतुलित हो जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बारिश के मौसम में जब गड्ढों में पानी भर जाता है, तो उन्हें देख पाना और भी मुश्किल हो जाता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना और भी बढ़ जाती है।

सरकारी अधिकारियों द्वारा इन गड्ढों की उपेक्षा ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। इन गड्ढों को समय पर नहीं भरा गया तो यह सड़क की संरचना को कमजोर कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

अब इस गंभीर समस्या को हल करने की जिम्मेदारी स्थानीय एनजीओ और नागरिक समाज पर है। हमें इन गड्ढों को भरने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। सिविल सोसाइटी और स्थानीय एनजीओ के प्रयासों से ही हम इन गड्ढों को समय रहते भर सकते हैं। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी, बल्कि सड़कों की स्थिति भी बेहतर होगी। आइए, हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं और सड़क सुरक्षा के इस मुद्दे को प्राथमिकता दें।

समय पर गड्ढों को भरकर हम न केवल अपनी सड़कों को सुरक्षित बना सकते हैं, बल्कि अनमोल जीवन को भी बचा सकते हैं। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा!

फ़रीदाबाद में एक सराहनीय पहल: स्वेच्छा से गड्ढे भरने का नेक कार्य

फ़रीदाबाद में हाल ही में एक बेहद सुंदर और प्रेरणादायक पहल देखने को मिली है। यहाँ स्थानीय लोगों ने स्वंयसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया है। यह कदम उन गड्ढों के खिलाफ उठाया गया है, जो न केवल सड़कों को खराब करते हैं बल्कि दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं।

इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इसमें शहर के आम नागरिक, स्वंयसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर बिना किसी सरकारी सहायता के गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। यह न केवल समाज में जागरूकता का प्रतीक है, बल्कि एकजुटता और जिम्मेदारी का भी उत्कृष्ट उदाहरण है।

लोगों ने अपनी इच्छा और प्रयासों से इस नेक कार्य की शुरुआत की है, जो निश्चित रूप से अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इस तरह की पहलों से न केवल सड़कों की स्थिति सुधरेगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।

फ़रीदाबाद में यह पहल यह संदेश देती है कि जब समाज एकजुट होकर किसी समस्या का समाधान करने का संकल्प लेता है, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आइए, हम सभी इस नेक प्रयास का समर्थन करें और अपनी सड़कों को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए आगे आएं।

भुवनेश्वर बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से करीब 80 किलो सोना और डेढ़ क्विंटल चांदी जब्त की गई है

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेश्वर : भुवनेश्वर बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बड़ी मात्रा में सोना और चांदी जब्त किया गया। शहर के जीएसटी विभाग ने दो कंटेनरों में ले जाए जा रहे सोने और चांदी को जब्त कर लिया। करीब 80 किलो सोना और डेढ़ क्विंटल चांदी जब्त की गई है । जिसकी अनुमानित कीमत 300 करोड़ से ज्यादा होगी ।बैंकों से एटीएम तक पैसे निकालने के लिए जिस लेन का उपयोग किया जाता है, उसी लेन में परिचालन होता है। इस वाहन में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वाहन को खोलना कठिन है और इसे वाहन के प्रभारी लोग ही खोल सकते हैं। हालांकि, इस वाहन में सोना ले जाने को लेकर सवाल खड़ा हो गया है कि ऐसे सोने का कारोबार बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से किया जा रहा है । लेन-देन के पीछे कौन है, इसका पता लगाने के लिए सिटी जीएसटी टीम ने चैनविन को लॉन्च किया है ।इसी तरह रुपयों की कीमत 5 करोड़ रुपये आंकी गई है ।

मनमोहन सामल ने कहा ममता महांत बीजेपी का राज्यसभा उम्मीदवार

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर : राज्यसभा के लिए सिर्फ एक सीट खाली होने से एक ही पार्टी से दो उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा रही । ऐसे में ममता की उम्मीदवारी खारिज होने का खतरा था, इसलिए ऐसी अफवाहें थीं कि बीजेपी ने जगन्नाथ को उम्मीदवार बनाया है । इस बीच इस मुद्दे पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है । ममता राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा की पार्टी की उम्मीदवार थीं और पार्टी का उम्मीदवार अंतिम था। मनमोहन के बयान के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद गरमा गया है । हालांकि, बीते 21 तारीख को ममता महंत ने बीजेपी की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था । पिछले महीने की 31 तारीख को बीजे से इस्तीफा देने के एक दिन बाद अगस्त महीने में ममता बीजेपी में शामिल हो गई थीं । हालांकि, 21 अगस्त को प्रदेश बीजेपी में एक बड़ा मोड़ देखने को मिला. 2024 के विधानसभा चुनावों में, जगन्नाथ प्रधान, जिन्होंने भुवनेश्वर-मध्य सीट से भाजपा के विधायक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन एक संकीर्ण अंतर से हार गए, ने दूसरे उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

दिल्ली में इतना सस्ता घर, 5 दिन में आए 20 हजार से ज्यादा आवेदन; मकान खरीदने पर मिल रही बंपर छूट

राजधानी दिल्ली में इतना सस्ता घर मिल रहा है कि पांच दिन में 20 हजार से ज्यादा आवेदन आ गए हैं। साथ ही इन मकानों को खरीदने पर बंपर छूट भी मिल रही है। जहां आमजन को 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी तो वहीं सरकारी नौकरी वालों को 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। DDA Housing Schemes के बारे में आगे विस्तार से पढ़िए।

नईदिल्ली। इसे इंटरनेट मीडिया चल रहे विज्ञापनों का असर कहें या फिर फ्लैटों DDA Flats में सुधार, लेकिन अबकी बार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए DDA) की तीनों नई आवासीय योजनाओं के प्रति लोगों में उत्साहजनक रुख देखने को मिल रहा है। काफी संख्या में लोग अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। बता दें कि सस्ता घर व मध्यमवर्गीय योजना के लिए गुरुवार से जबकि द्वारका ई-नीलामी योजना के लिए बुधवार से पंजीकरण चल रहा है। डीडीए DDA से मिली जानकारी के मुताबिक, सस्ता घर योजना के लिए पांच दिनों में ही दिन 2,2055 लोग पंजीकरण करा चुके हैं। मध्यम वर्गीय योजना के लिए 1,189 लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है। द्वारका ई-नीलामी योजना के लिए छह दिन में 700 लोगों ने पंजीकरण कराया है।

सीरवी समाज पारसीगुटा बडेर अध्यक्ष बने मोहनलाल हाम्बड़ सचिव बने नारायण लाल काग

परिवहन विशेष न्यूज

पारसीगुटा स्थित श्री आई माताजी बडेर में सीरवी समाज पारसीगुटा तेलंगाना की आगामी कार्यकाल के लिए नई कार्यकारिणी का चुनाव प्रक्रिया के तहत 25 अगस्त 36 एरिया सदस्यो द्वारा सीरवी समाज, सीरवी शिक्षा समिति व महिला

मंडल के पदाधिकारियों का गठन किया गया। प्रेस विज्ञप्ति में अध्यक्ष चोलाराम हाम्बड़ व चुनाव अधिकारी बाबूलाल मुलेवा ने बताया कि सीरवी समाज तेलंगाना की नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसहमति से चुनाव प्रक्रिया के तहत किया गया गया। चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी

मल्लाराम सेपटा एवं बाबूलाल मुलेवा व सहायक सीए जस्साराम बर्फा को दी गयी। सर्वसहमति से चुने गये पदाधिकारियों में सीरवी समाज नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनलाल हाम्बड़, उपाध्यक्ष-1 मूलाराम चोयल, उपाध्यक्ष- 2 रमेश पंवार, सचिव नारायणलाल काग, सहसचिव हीरालाल खंडाला, कोषाध्यक्ष खंगार सिंह लचेटा, शिक्षा समिति नवनिर्वाचित अध्यक्ष लाबुराम पंवार, उपाध्यक्ष 1 मांगीलाल हाम्बड़, उपाध्यक्ष- 2 वोराराम भायल, सचिव चेलाराम भायल, सहसचिव रमेश परिहार, कोषाध्यक्ष हिम्मताराम हाम्बड़, खेल मंत्री हिम्मताराम हाम्बड़, महिला मंडल नवनिर्वाचित अध्यक्षा सुशीला देवड़ा, उपाध्यक्षा- 1 इन्द्रा देवी आगलेचा, उपाध्यक्षा 2 अनिता देवी

चोयल, सचिव निर्मला देवड़ा, सहसचिव कविता सोलंकी, कोषाध्यक्षा नीलू लचेटा प्रमुख रूप से रहे। तीनों कमिटियों एवं सभी एरिया सदस्य को प्रमाण पत्र प्रदान कर एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने पर चुनाव अधिकारियों का पुष्प-मालाओं से विशेष सम्मान किया गया। सर्वसहमति से अध्यक्ष चुने जाने पर मोहनलाल हाम्बड़,

लाबुराम पंवार व सुशीला देवड़ा ने समाज बन्धुओं का तहदिल से आभार प्रकट करते हुए भरोसा दिलाया कि सभी के सहयोग से समाज के विकास के लिए वे हर सम्भव प्रयास करेंगे। अध्यक्ष चोलाराम हाम्बड़ ने चुनाव प्रक्रिया में समाज बन्धुओं द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग करने के लिए आभार प्रकट किया। मंच का संचालन करते हुए सचिव किशनसिंह राठौड़ ने बताया कि आगामी कार्यकाल के लिए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को भादवा सुदी बीज गुरुवार 5 सितंबर को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाकर वर्तमान पदाधिकारियों को विदाई देते हुए कार्यभार सौंपा जाएगा। पधारे समाज बन्धुओं के लिए भोजन-प्रसादी की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर की गयी (छाया विवरण जगदीश सीरवी)

सीरवी समाज ट्रस्ट आईलापुर बिरमगुड़ा का वार्षिक सम्मेलन 5 सितंबर को

परिवहन विशेष न्यूज

सीरवी समाज ट्रस्ट आईलापुर,बिरमगुड़ा स्थित सीरवी समाज की आस्था का केन्द्र श्री आईमाता मंदिर में समाज बन्धुओं के सानिध्य में विशेष मीटिंग आयोजितकर श्री आईमाताजी के 609 वें अवतरण दिवस व 4 वा वार्षिक सम्मेलन पर दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत भादवा सुदी एकम बुधवार 4 सितंबर रात्रि जागरण व भादवा सुदी बीज (दूज) गुरुवार 5 सितंबर प्रातः वेला में पूजा- अर्चना व महाप्रसादी कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया जायेगा।

अध्यक्ष कन्हैयालाल बर्फा, उपाध्यक्ष राकेश चोयल,सचिव मोहनलाल भायल महासभा उपाध्यक्ष माणकचन्द गेहलोत ने संयुक्त रूप से बताया कि हर वर्ष की भांति समाज बन्धुओं के सानिध्य में दो दिवसीय भादवा सुदी बीज महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बुधवार 4 सितंबर प्रातः वेला में श्री आईमाता मंदिर को विशेष फूलों व लाइटिंग से सजाकर माई का विशेष श्रृंगारकर रात्रि 9.11बजे से जागरण आयोजित किया जाएगा। जिसमे भगत भजन मण्डली भैराराम सैणचा व भुराराम सैणचा माई के चरणों में भजनों के पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश वंदना एवं आईमाता जी पुजा अर्चना श्री आईमाता जी की पूर्ण आरती गुरुवार 5 सितंबर प्रातः 9.15 बजे ज्योत प्रज्वलितकर, पुजा अर्चना, स्वागत, समाज बन्धुओं द्वारा माई के चरणों में श्रीफल भेंटकर परिवार के सुख-समृद्धि की कामना, , प्रातः 10 बजे से धर्मसभा का आयोजनकर अध्यक्ष कन्हैयालाल बर्फा की अध्यक्षता में मुख्य अतिथियों, पधारे मेहमानों का स्वागत, कोषाध्यक्ष मल्लाराम सोलंकी द्वारा आय-व्यय का विवरण, पदाधिकारियों का सम्मान एवं अपने विचार व्यक्त करना, सचिव मोहनलाल भायल द्वारा समाज में किये गये विकासशील कार्यो का विवरण, एवं पधारे समाज बन्धुओं व भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था मंदिर प्रांगण में रहेगी। बीज महोत्सव कार्यक्रम में पदाधिकारी व कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य पधारे भक्तों की सेवार्थ उपस्थित रहेंगे। समाज बन्धुओं से निवेदन है कि बीज महोत्सव पर अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर, समाज बन्धु सपरिवार पधारकर कार्यक्रम का लाभ लेवे। अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन भाषण व धन्यवाद प्रस्ताव, महाआरती के पश्चात कार्यक्रम का समापन्न होगा।

प्रो. डॉ. अब्दुल अकील डि.एस.सी (डॉक्टर ऑफ साइंस) से सम्मानित

सुषमा रानी । अमरावती : प्रो. डॉ. अब्दुल अकील को International Kingdom University Florida, अमेरिका तथा सि.बी.आ. यूनिवर्सिटी अफ्रीका ने एल.एल.डी (Doctor of Law) से और UNIAGSFMI International Open University Venezuela ने डि.एस.सी (Doctor of Science) से सम्मानित किया है। इस अवसर पर 2 व्यक्ति को डीलिट एवं एक व्यक्ति को एल एल डी, एक व्यक्ति को डी इस सी की डिग्री प्रदान की गई यह सम्मान अध्यक्ष अनिल भट्कर, विजय रावत डायरेक्टर एनीमेशन कॉलेज अमरावती महाराष्ट्र, मोहम्मद जिलानी रिटायर्ड सिविल सर्जन, डॉक्टर स्पीच डॉक्टर बी जी खोबरागड़े रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा यह सम्मान दिया गया। इस अवसर पर मुंबई से डॉक्टर अशफ़ाक उमर, तबस्सुम मनजूर नाडकर, नाजिमा रहबरी, के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

राज्य भाजपा ने दैनिक समाचार पत्र "ओडियार सन्मान" की संपादक सामंथा मोहंती के निधन पर शोक व्यक्त किया

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा, भुवनेश्वर, दैनिक समाचार पत्र ऑडिआर सन्मान की संपादक श्रीमती कनिता मोहंती का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रदेश अध्यक्ष श्री मनमोहन सामल ने स्वर्गीय मोहंती को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत मोहंती एक धर्मपरायण और परोपकारी महिला थीं। प्रदेश अध्यक्ष श्री सामल ने दिवंगत मोहंती की अमर आत्मा की कामना करते हुए भगवान श्रीजगन्नाथ से ऐसी दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिवार एवं पंथजन को असीम धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की है।

डॉ. शगुन गुप्ता की दिल्ली यात्रा ने पर्मानेन्ट मेकअप और एंटी-एजिंग उपचारों की बढ़ती लोकप्रियता पर डाली रोशनी

सुषमा रानी

दिल्ली ने हाल ही में भारत की सबसे मशहूर पर्मानेन्ट मेकअप, एंटी-एजिंग स्किनकेयर, और माइक्रोपिगमेंटेशन विशेषज्ञ, डॉ. शगुन गुप्ता की मेज़बानी की। अपनी व्यावसायिक यात्रा के दौरान, डॉ. गुप्ता ने कई न्यूज़ चैनलों पर उपस्थिति दर्ज कराई, जहाँ उन्होंने पर्मानेन्ट मेकअप के बढ़ते चलन और इसे मुख्यधारा की सुंदरता और स्किनकेयर में मिल रही स्वीकार्यता पर जोर दिया।

डॉ. शगुन गुप्ता, जिनके पास इस क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव है, ने फिल्म और टेलीविज़न उद्योग के कई प्रसिद्ध हस्तियों के साथ काम किया है। उनके प्रभावशाली ग्राहकों की सूची में फ्रेडी दारूवाला, राइमा सेन, काम्या पंजाबी, अर्शी खान, शायरा खान, जसलीन मथारू, और पूनम पांडे जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। ये हस्तियां, जो हमेशा चर्चा में रहती हैं, अपने शानदार दिखने के लिए डॉ. गुप्ता की विशेषज्ञता पर निर्भर रहती हैं। डॉ. गुप्ता कहती हैं, "सेलिब्रिटीज़ यह समझते हैं कि हर समय अच्छा दिखना कितना महत्वपूर्ण है, और पर्मानेन्ट मेकअप एक ऐसा साधन है जो उन्हें बिना किसी मेहनत के यह हासिल करने में मदद करता है।"

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन यह सिर्फ़ सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी इस तरह के उपचार से सेलिब्रिटी की तरह दिख सकता है। पर्मानेन्ट मेकअप और एंटी-एजिंग स्किनकेयर उपचार कुछ ऐसा है जो हर किसी को आज़माना चाहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है; वास्तव में, यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को काफी बढ़ा सकता है।"

पर्मानेन्ट मेकअप, जिसे माइक्रोपिगमेंटेशन के रूप में भी जाना जाता है, त्वचा पर पिगमेंट्स का उपयोग करके भौंहें, होंठ और आईलाइनर जैसी विशेषताओं को निखारने का काम करता है। इस तकनीक से, जब इसे डॉ. गुप्ता जैसे कुशल पेशेवर द्वारा किया जाता है, तो यह वर्षों तक चलने वाले प्राकृतिक दिखने वाले परिणाम दे सकता है। कम रखरखाव वाली सुंदरता समाधान की बढ़ती मांग के साथ, अधिक से अधिक लोग अपनी विशेषताओं को निखारने के लिए पर्मानेन्ट मेकअप का सहारा ले रहे हैं ताकि उन्हें दैनिक टच-अप की आवश्यकता न पड़े।

एंटी-एजिंग उपचार अक्सर संदेह के साथ देखे जाते हैं, कई लोग इसे घमंड या अनिच्छा से उम्र को स्वीकार करने के साथ जोड़ते हैं। हालाँकि, डॉ. गुप्ता इस धारणा को बदलने के मिशन पर हैं। ₹हर कोई सुंदर दिखना और अपनी त्वचा में आत्मविश्वास महसूस करना चाहता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एंटी-एजिंग स्किनकेयर उपचार आपके प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने और उम्र बढ़ने के साथ आपकी त्वचा की देखभाल करने के बारे में हैं। यह आपको बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके सर्वश्रेष्ठ संस्करण को सामने लाने के बारे में है," वह समझाती हैं।

एंटी-एजिंग उपचारों के प्रति डॉ. गुप्ता का दृष्टिकोण व्यापक है, जो उन्नत तकनीक को स्किनकेयर की गहरी समझ के साथ जोड़ता है। उनके उपचार झुर्रियों, महीन रेखाओं, और त्वचा की झुर्रियों जैसे उम्र बढ़ने के विभिन्न लक्षणों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे उनके ग्राहकों को एक युवा और चमकदार उपस्थिति प्राप्त होती है। "मेरा लक्ष्य है कि लोग अपने बारे में अच्छा महसूस करें, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। सही उपचार के साथ, कोई भी युवा और अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकता है," वह कहती हैं।

सौंदर्य उद्योग में अपने कार्य के अलावा, डॉ. शगुन गुप्ता एक समर्पित परोपकारी भी हैं। वह शगुन गुप्ता फाउंडेशन चलाती हैं, जो महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। यह फाउंडेशन शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से वंचित समुदायों को बेहतर जीवन बनाने में मदद करता है।

"सशक्तिकरण कई रूपों में आता है, और मेरे लिए, यह लोगों को सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन प्रदान करने के बारे में है। शगुन गुप्ता फाउंडेशन के माध्यम से, हम उन लोगों के लिए अवसर पैदा करने का प्रयास करते हैं जिन्हें हाशिए पर रखा गया है, विशेष रूप से महिलाएं और ट्रांसजेंडर्स,₹ डॉ. गुप्ता कहती हैं।

फाउंडेशन के साथ उनका काम उनकी इस धारणा को दर्शाता है कि सुंदरता और आत्मविश्वास सशक्तिकरण के साथ मिलकर चलते हैं। व्यक्तियों को सुंदर और आत्मविश्वासी दिखने और महसूस करने में मदद करके, वह उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने और अपने सपनों का पीछा करने में भी मदद कर रही हैं।

डॉ. शगुन गुप्ता की दिल्ली यात्रा ने एक बार फिर पर्मानेन्ट मेकअप और एंटी-एजिंग उपचारों में उनकी विशेषज्ञता को उजागर किया है। एक ऐसी ग्राहक सूची के साथ जिसमें मनोरंजन उद्योग के सबसे प्रसिद्ध चेहरे शामिल हैं, डॉ. गुप्ता ने सौंदर्य और स्किनकेयर की दुनिया में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अपने क्लिनिक में और अपने फाउंडेशन के माध्यम से किए गए अपने काम के माध्यम से, वह लगातार व्यक्तियों को उनके सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखने और महसूस करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, यह साबित करते हुए की सुंदरता वास्तव में असीमित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023